https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

28 द इकनॉमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव, कुआलालंपुर

वर्ष-12, अंक-01, 01-15 जनवरी, 2017 (पाक्षिक) ₹20

‘नोटबंदी से आए धन के बाद तेजी से होगा देश का विकास’

बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर, छत्तीसगढ़

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत

संकट नहीं समाधान है नोटबंदी

वाराणसी (उप्र) प्रवास के दौरान भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं एवं जनता से संवाद करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

जनसभा मैदान में पार्टी नेताओं के साथ सहभोज के दौरान

वाराणसी (उप्र) में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, साथ में - केंद्रीय मंत्रीगण डॉ.महेश शर्मा, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री महेंद्र पांडेय एवं अन्य पार्टी नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'अन्न वितरण प्रणाली के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे शीर्ष पर'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तेरह साल के शासन में...

वैचारिकी

जीवन का ध्येय 14

श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अग्रदूत 16

ब्लॉग

पार्टी का ग्रंथालय : राजनीति की संस्कारशाला 18

लेख

सुशासन की सबसे बड़ी प्रेरणा 20
विमुद्रीकरण सम्बन्धी तथ्य 22
संकट नहीं समाधान है नोटबंदी 24
न्यायालय ने की तीन तलाक पर सुनवाई 26

परिवर्तन रैलियां

कानपुर (उप्र) 30
एटा (उ.प्र.) 31

अन्य

लोक सभा से 4 और राज्य सभा से 1 विधेयक पारित 17
'मलेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध हमारी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का अभिन्न हिस्सा' 28
कारोबार को आसान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम 32
'नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रगतिकामी कदम उठा रहे हैं' 33

संगठनात्मक गतिविधियां

08 **'मोदी सरकार ने नोटबंदी से किया ऑपरेशन'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को हिमाचल...

09 **चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत**

चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा और अकाली गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर कांग्रेस...

सरकार की उपलब्धियां

11 **निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 पारित**

दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाने और संयुक्त राष्ट्र समझौते...

12 **लक्की ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना का शुभारंभ**

सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में भ्रष्टाचार और काले धन के अभिशाप से निपटने के लिए...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। यह हमारी सामरिक रक्षा को जबरदस्त मजबूती प्रदान करेगी।

@rajnathsingh

जिस विकास और सुशासन को सपा और बसपा की सरकारों ने वनवास दे दिया था, हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर उसकी घर वापसी करायेंगे।

@arunjaitley

संसद में बहस को रोके रखने के लिए अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच परस्पर प्रतियोगिता हो रही है।

@naqvimukhtar

हर हाथ को काम मोदी सरकार का संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

facebook

अखिलेश यादव कहते हैं कि यदि कांग्रेस हमारे साथ आ जाए तो यूपी में शायद फिर से हमारी सरकार आ जाए, मैं उनसे कहता हूं कि बुआ को क्यों छोड़ते हो? बुआ-भतीजा, राहुल सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आपको मार्च ही निकालना है तो रोजगार के लिए निकालिए, भुखमरी के खिलाफ निकालिए, गांवों तक बिजली, सड़क पहुंचाने के लिए निकालिए, पर कम से कम काले धन को बचाने के लिए तो मत निकालिए। **- अमित शाह**

पर्यटन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वदेश दर्शन योजना में आध्यात्मिक परिपथ एवं विरासत परिपथ से जुड़े स्थानों का त्वरित गति से विकास किया जा रहा है। इसी के अन्तर्गत मेरठ, बिजनौर, कैराना एवं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास निर्धारित है। आध्यात्मिक परिपथ एवं विरासत परिपथ से जुड़े इन कार्यों के पूर्ण होने से तीर्थाटन को बल मिलेगा और आम लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाओं का विकास होगा। **- महेश शर्मा**

पाथेय

हम नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करने का संकल्प लें। हमारे लिए राजनीति सदैव उच्च मिशन रही है, हमने इसे एक महान लक्ष्य को साधने के लिए छोटे से साधन के रूप में अपनाया है: एक समृद्ध समाज, जो भेदभाव से मुक्त हो, एक ऐसा समाज, जहां प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे और एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद और धार्मिक उन्माद की बुराइयां न हों।

हमारी पार्टी सचमुच ही राष्ट्रवादी पार्टी है, क्योंकि हम राष्ट्र को किसी भी चीज के ऊपर रखते हैं।

एक राजनीतिक पार्टी का जन्म एक राजनीतिक विचार से होता है। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी है, राष्ट्रवाद के विचार से उत्पन्न हुई है। यह हमारी विचारधारा का मूलतंत्र है। हमारे लिए भारत एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति है।

-कुशाभाऊ ठाकरे

कांग्रेस का पतन सुनिश्चित

अब जबकि स्वयं कांग्रेस एवं विपक्ष का एक वर्ग संसद की कार्यवाही बाधिक करता रहा, राहुल गांधी के 'भूकंप' से देश बच गया। इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर कांग्रेस पूरे देश में हंसी की पात्र बन गई। यदि राहुल गांधी के पास सचमुच 'भूकंप' जैसा कुछ था तो कांग्रेस ने पूरे सत्र संसद को रोके क्यों रखा? और यदि वे इस मुद्दे पर ईमानदार थे, तब संसद में चर्चा की मांग क्यों नहीं की? यह 'भूकंप' तो मीडिया द्वारा भी लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ वे कर नहीं पाये। असल में शायद अब तक राहुल गांधी समझ नहीं पाए कि वे राजनीति कर रहे हैं, ठिठोली नहीं। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे देश हिल जाता। हां वे चाहते जरूर थे कि वास्तविक मुद्दों से देश भटक जाये। कांग्रेस की सरपरस्ती में इस देश में जमा काला धन, बड़े-बड़े घपले एवं घोटाले जिससे इस देश की जनता का धन लूटा गया, निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा बुना गया समानांतर अर्थतंत्र का जाल तथा कांग्रेस काल में बना भारी-भरकम लूटतंत्र अब कांग्रेस का पीछा कर रही है। जन-जन के द्वारा जो समर्थन विमुद्रीकरण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिल रहा है, उसने कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। कांग्रेसी लूटतंत्र में विकसित निहित स्वार्थी तत्वों को राहुल गांधी आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे अब भी उनका हित सुरक्षित रख सकते हैं।

वंशवाद की जंजीर ने कांग्रेस के हाथ-पांव बांधकर उसे पंगु बना दिया है। अब जबकि देश के पास संघर्ष की भट्टी से तपकर निकला नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में मौजूद है। वंशवादी राजनीति में जकड़ी कांग्रेस आये दिन अपमान झेलने पर मजबूर होगी ही। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा झूठ-फरेब एवं झांसे की राजनीति का सहारा लेने से उसका पतन एवं पराजय सुनिश्चित हो चुका है।

राहुल गांधी के कारण जब-तब कांग्रेस को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। बार-बार आधारहीन एवं बेतुका बयान देकर वे कांग्रेस के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष बनने की जगह वे कांग्रेस को उस राह पर धकेल रहे हैं, जहां से उसे लौटना मुश्किल है। अब तक तो उन्हें समझ लेना चाहिए था कि झूठ और फरेब की राजनीति के हाथ-पांव नहीं होते। इस तरह की राजनीति से पार्टी का दिवालियापन ही जनता के सामने बार-बार आ रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी उठाने से बचने के लिए कांग्रेस देश को गुमराह करने के लिये तरह-तरह की झूठी कहानियां गढ़ने में लगी है, लेकिन जनता अब पूरी तरह से जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है यही कारण है उसे जनता के द्वारा कठोर से कठोर दंड भुगतना पड़ रहा है। यदि हाल में देश भर में हुए उपचुनावों यथा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं चंडीगढ़ के स्थानीय निकायों के चुनावों से कांग्रेस कोई सबक ले सकती है, तब उसे दिल पर हाथ रखकर अपनी करतूतों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेसी संस्कृति को सुधारने की जगह इसके नेतृत्व द्वारा घपलेबाजों, भ्रष्टाचारियों, हवाला कारोबारियों के हितों को बनाये रखने की जद्दोजहद से कांग्रेस का असली चरित्र पुनः उजागर हुआ है।

लोकतंत्र में जनता ही किसी भी पार्टी का भाग्य लिखती है। जन समर्थन पार्टी एवं नेतृत्व की विश्वसनीयता के आधार पर ही तय होता है। भाजपा एवं इसके नेतृत्व की विश्वसनीयता वर्षों की कठोर परीक्षा, वैचारिक प्रतिबद्धता एवं अथक प्रयासों से सुदृढ़ हुई है। कांग्रेस के विपरीत भाजपा का नेतृत्व पारिवारिक या वंशानुगत राजनीति द्वारा तैयार नहीं हुआ है। भाजपा नेतृत्व वैचारिक कार्यप्रणाली, मूल्य आधारित राजनीति, राष्ट्रीय निष्ठा तथा सुशासन एवं विकास के प्रति समर्पण के आधार पर तैयार हुआ है। यदि किसी पार्टी का नेतृत्व वंश एवं परिवार आधारित हो जाय तो उसका भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। वंशवाद की जंजीर ने कांग्रेस के हाथ-पांव बांधकर उसे पंगु बना दिया है। अब जबकि देश के पास संघर्ष की भट्टी से तपकर निकला नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में मौजूद है, वंशवादी राजनीति में जकड़ी कांग्रेस आये दिन अपमान झेलने पर मजबूर होगी ही। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा झूठ-फरेब एवं झांसे की राजनीति का सहारा लेने से उसका पतन एवं पराजय सुनिश्चित हो चुका है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

अन्न वितरण प्रणाली के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे शीर्ष पर : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तेरह साल के शासन में इसे बीमारू राज्य से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश के हर कोने में पार्टी सांसद और सबसे ज्यादा विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता सकते हैं कि देश में सबसे ज्यादा विकास करने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। नोटबंदी से आए धन के बाद देश का विकास बेहद तेजी से होगा। श्री शाह ने आवाहन किया कि छत्तीसगढ़ बूथ के कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेन्द्र मोदी और श्री रमन सिंह का संदेश पहुंचाएं।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता था। अब सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार है। यहां विकास को गांवों तक पहुंचाना बहुत कठिन था। तेरह साल में रमन सिंह सरकार ने इस काम को बहुत अच्छे से किया। गरीब, दलित, आदिवासी सबको विकास में उचित स्थान मिला। सर्वसमावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण रमन सिंह जी ने दिया है।

> तेरह साल में रमन सिंह सरकार में गरीब, दलित, आदिवासी सबको विकास में उचित स्थान मिला। सर्वसमावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण रमन सिंह जी ने दिया है।

छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार जैसा काम कर रही है, चौथी बार भी वही आएगी। अन्न वितरण प्रणाली के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे शीर्ष पर है। श्री रमन सिंह को पहली सरकार के लिए सात हजार करोड़ का बजट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इसे 70 हजार करोड़ तक पहुंचाया है। छत्तीसढ़ सरकार ने 13 साल में कई उपलब्धियां हासिल कीं। प्रति व्यक्ति आय दस हजार से आठ गुना बढ़ाकर 82 हजार रुपये तक पहुंच गई है। बिजली का उत्पादन भी 4732 मेगावाट से बढ़कर अब 22764 मेगावाट हो रहा है। राज्य सरकार ने विकास के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और गरीब की पीड़ा को समझने का काम किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तीन पैमाने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब शिशु मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों में 63 था। जिसे राज्य सरकार 43 पर ले आई है। मातृ मृत्यु दर भी एक लाख पर 365 थी जो घटकर 221 पर आ गई है। कुपोषण 52 फीसदी था जो अब घटकर 30 फीसदी से भी कम हो गया है। करीब 59

हजार किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क तैयार करने का काम किया गया है। पहले 29 लाख टेलीफोन थे अब एक करोड़ 59 लाख टेलीफोन हैं। नक्सलवाद से पीड़ित राज्य में श्री रमन सिंह ने कठोर निर्णय लेते हुए लगभग नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। रमन सिंह ने आदर्श गरीब कल्याण सरकार देने का काम किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी और आज हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन हैं। पार्टी के पास 11 करोड़ सदस्य हैं। पहले इस पार्टी को कुछ राज्यों में सिमट जाने वाला माना जाता था। आज गुजरात के कच्छ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से है और असम के कामरूप का सांसद भी। कश्मीर के लेह लद्दाख का सांसद भी इस पार्टी का है और कन्याकुमारी का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा 14 राज्यों में पार्टी के मुख्यमंत्री या पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है तो यह श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह काम किया है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय और विश्वस्त बनकर उभरे हैं।

कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूछते हैं कि ढाई साल के शासन में आपने देश को क्या दिया। राहुल जी, हमने देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपके प्रधानमंत्री की आवाज तो सिर्फ आप और आपकी मां ही सुन पाती थीं। हमारे प्रधानमंत्री देश की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर मुखर होकर लोगों से बात करते हैं। दस साल तक सोनिया-मनमोहन सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले किए। ढाई साल में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। सरकार में पूरी पारदर्शिता है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कश्मीर में सीमापार से आए दिन गोली चलती थी लेकिन सैनिकों के पास गोली चलाने का अधिकार नहीं था वह दिल्ली की राह देखते थे। आज श्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सीमापार से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। सैनिकों को पूरी छूट है। उरी में सोते हुए जवानों पर हमला किया गया। पूरे देश में गहरी हताशा थी लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं श्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाब दिया।

श्री शाह ने कहा कि आठ तारीख तक सारे विपक्षी दल पूछते थे कालेधन के लिए क्या किया अब पूछते हैं यह क्यों किया। कालेधन पर जिन लोगों के 70 साल की कमाई रद्दी हो गई वही परेशान हैं। कांग्रेस ने देश को कालेधन का लकवा दिया था। जिसका श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ऑपरेशन कर रही है। लोगों की परेशानी को सरकार समझती है लेकिन इस बीमारी का ऑपरेशन बेहद जरूरी था। कालेधन को बैंक में जमा करने वाले भी बच नहीं पाएंगे उनसे 50 फीसदी कर और 25 फीसदी गरीब कल्याण योजना के लिए लिया जाएगा। कालाधन छुपाने वालों से 85 फीसदी लिया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चार तरह की सरकारें आईं। पहली कांग्रेस, दूसरी कम्युनिस्ट, तीसरी क्षेत्रीय दल और चौथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश के राजनीतिक विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों के सामने सारे आंकड़े मौजूद हैं। यह विशेषज्ञ विकास, राज्य को आगे बढ़ाने, कानून व्यवस्था बेहतर करने, सामाजिक सशक्तीकरण और महिला सशक्तीकरण को आधार बनाकर विश्लेषण करें। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि सबसे बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हम जातिवाद, संकुचित प्रदेशवाद, सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस की राजनीति करते हैं। सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। श्री दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और श्री नरेन्द्र मोदी की 'सबका साथ सबका विकास' का मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बार-बार जनता उसे लेकर आई है। ■

भाषण के प्रमुख बिन्दु

- भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तेरह साल के शासन में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है।
- अन्न वितरण प्रणाली के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे शीर्ष पर है।
- कांग्रेस ने दिया देश को कालेधन का लकवा, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी से ऑपरेशन किया ।
- राहुल गांधी को नहीं दिखते नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, भ्रष्टाचार विहीन शासन जैसे बड़े कदम, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं।
- मनमोहन सिंह ने किए श्री नरेन्द्र मोदी से ज्यादा विदेशी दौरे, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी को ज्यादा प्यार और समर्थन मिला।
- भारतीय जनता पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।
- गुजरात के कच्छ से लेकर असम के कामरूप तक, कश्मीर के लद्दाख से कन्याकुमारी तक हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद।
- पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एक हजार से अधिक विधायक, सबसे ज्यादा 14 राज्यों में पार्टी की या पार्टी के समर्थन से सरकार।
- पूरे देश में सबसे बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। राजनीतिक विश्लेषक कर सकते हैं विश्लेषण।

'कांग्रेस ने दिया देश को कालेधन का लकवा, मोदी सरकार ने नोटबंदी से किया ऑपरेशन'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सफाये के साथ ही पूरा होगा। नोटबंदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस की दी गई बीमारी का ऑपरेशन बताया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तरह नेताओं, घरानों और जातियों के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। यह संगठन और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। बूथ कार्यकर्ता इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल ने कभी गरीबी नहीं देखी और वह गरीबों का दर्द समझ भी नहीं सकते। केंद्र की 90 से ज्यादा विकास योजनाओं के बाद भी उन्हें बदलाव समझ नहीं आ रहा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्राणतत्व संगठन है और संगठन का प्राणतत्व बूथ कार्यकर्ता हैं। बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं। कार्यकर्ता सजग, उत्साहित और परिवर्तन का संकल्प लेने वाला है, इसलिए परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है बूथ के कार्यकर्ताओं को जागरुक और संगठित करती है। हम संगठन के बूते ही चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यूपी, उत्तराखंड होता हुआ हिमाचल प्रदेश आएगा। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार करने में अहम योगदान दें। हिमाचल प्रदेश में आवन-जावन की परंपरा खत्म कर 20 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।

> भारतीय जनता पार्टी का प्राणतत्व संगठन है और संगठन का प्राणतत्व बूथ कार्यकर्ता हैं। बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं। कार्यकर्ता सजग, उत्साहित और परिवर्तन का संकल्प लेने वाला है, इसलिए परिवर्तन तय है।

श्री शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नीत सरकार केंद्र की योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचने नहीं दे रही है। राज्य सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार सूचकांक बनाया जाए, तो हिमाचल प्रदेश देश में शीर्ष पर होगा। भ्रष्टाचार का पैसा सीधा मुख्यमंत्री के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कार्यकर्ताओं को हर बूथ, हर पहाड़ और हर चोटी पर इतना परिश्रम करना है कि समयपूर्व चुनाव की नौबत आ जाए और राज्य को इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिले।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार गरीबों के हित के सवाल उठाते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी गरीबों के दर्द को नहीं समझा। कांग्रेस ने 17 सालों में 92 लाख गैस कनेक्शन बांटे, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पांच करोड़ गैस कनेक्शन ग्रामीणों को देने का लक्ष्य रखा इसमें से एक करोड़ कनेक्शन तो अब तक बंट भी चुके हैं। अब तक 17 हजार करोड़ रुपये की गैस सब्सिडी बचाई गई है। गिव इट अप योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवाहन पर एक करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। इन्हीं पैसों से उज्जवला योजना शुरू की गई। पहले एक महिला खाना बनाते हुए ही 400 सिगरेट के बराबर का धुंआ पी जाती थी। श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों की समस्या को नहीं समझ सकते, लेकिन जमीन से जुड़े प्रधानमंत्री ने योजनाओं को बनाते समय गरीबों के प्रति संवेदना का भी पूरा ध्यान रखा है। देश में 60 करोड़ लोगों के पास एक बैंक खाता भी नहीं था। हमने 20 करोड़ परिवारों के खाते खुलवाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष को सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, भ्रष्टाचार विहीन शासन जैसी बड़ी सफलताओं के बाद भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। वह अनर्गल आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उरी में आतंकियों ने सोते हुए भारतीय जवानों को निशाना बनाया। यूपीए के समय सेना को पहले सेनाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष को दिल्ली में बैठी सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार श्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। हमने सैनिकों को सीमापार से गोलीबारी होने की स्थिति में जवाबी फायरिंग करने की खुली छूट दी है। उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। ■

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत

नोटबंदी को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। इस फैसले के बाद हो रहे चुनावों में लोग भाजपा के प्रति भरोसा जता रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों तथा विधानसभा व लोकसभा उपचुनावों में भाजपा को शानदार सफलता मिली। अब चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा और अकाली गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। गत 20 दिसंबर को आए चुनाव परिणाम में भाजपा-शिअद गठबंधन ने 26 वार्ड में से 21 वार्ड में जीत हासिल की। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 20 स्थानों पर विजय प्राप्त की और एक सीट अकाली दल को मिली। कांग्रेस को सिर्फ चार सीटों से संतोष करना पड़ा। साल 1996 के बाद ये भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। पिछली बार हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा के 15 पार्षद थे, जबकि नौ कांग्रेस और एक स्वतंत्र पार्षद थे। ■

चुनाव परिणाम एक नजर में

कुल सीटें	26	कांग्रेस	04
भाजपा	20	बसपा	00
अकाली दल	01	अन्य	01

@narendramodi

भाजपा और अकाली दल को समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ के लोगों को धन्यवाद। यह दर्शाता है कि लोग सुशासन को महत्व देते हैं।

मोदीजी के विजन और भाजपा की 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' की नीति में जनता की अटूट आस्था: अमित शाह

चंडीगढ़ निगम चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने चंडीगढ़ की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा संगठन पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि डिमोनेटाईजेशन के फैसले के बाद संपन्न हुए हर चुनावों में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के फैसले पर मुहर लगाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों का जनता ने हृदय से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाईजेशन के फैसले के बाद संपन्न हुए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों और विधान सभा एवं लोक-सभा उप-चुनावों के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष डिमोनेटाईजेशन के फैसले का राजनीतिकरण करना चाहती है, इस पर राजनीति कर रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डिमोनेटाईजेशन के फैसले के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए सभी चुनावों में देश की जनता ने विपक्ष को यह अच्छे से समझाया है कि जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के विजन और भारतीय जनता पार्टी की 'पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस' की नीति में देश की जनता की अटूट आस्था और विश्वास का एक और उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि देश के सभी हिस्से में जहां-जहां भी डिमोनेटाईजेशन के फैसले के बाद चुनाव हुए हैं और जनता ने भाजपा को प्रचंड विजय दिलाते हुए प्रधानमंत्री के फैसले पर जो मुहर लगाई है, मैं इसके लिए एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ■

भाजपा राष्ट्रीय मोर्चो के अध्यक्षों की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 दिसंबर को पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, युवा मोर्चा एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की।

कौशांबी (उत्तरप्रदेश) से सांसद श्री विनोद सोनकर को अनुसूचित जाति मोर्चा और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद श्री रामविचार नेताम को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया।

किसान मोर्चे के अध्यक्ष पद पर भदोही (उत्तरप्रदेश) से सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त नियुक्त किए गए।

वहीं पूर्व सांसद श्री दारा सिंह चौहान अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए।

मुंबई उत्तर-मध्य (महाराष्ट्र) से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती पूनम महाजन को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया।

विनोद सोनकर

रामविचार नेताम

वीरेंद्र सिंह मस्त

दारा सिंह चौहान

पूनम महाजन

रंजीत दास बने असम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को श्री रंजीत दास को असम प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया।

पूर्व में पत्रकार रहे श्री दास असम प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और 1992 में वे भाजपा के सदस्य बने।

श्री दास सोरभोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें श्री सर्वानंद सोनोवाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद श्री सोनोवाल के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद श्री दास को नया अध्यक्ष चुना गया।

भाजपा में शामिल हुए हंसराज हंस

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के सान्निध्य में सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री हंसराज हंस ने 10 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री हंस ने कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के राष्ट्रहित एवं जनहित में लिए गए क्रांतिकारी फैसलों से प्रभावित होकर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व पटल पर अग्रणी बन कर उभर रहा है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। श्री हंस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उससे आज भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 पारित

दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाने और संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप 'निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016' को संसद ने 16 दिसंबर को पारित कर दिया। इससे दिव्यांगजनों के लिए समाज में सम्माननीय स्थान बनाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, पहली बार विधेयक में दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगों से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण विधेयक 'निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016' संसद द्वारा 16 दिसंबर को पारित कर दिया गया। इसमें निःशक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। विधेयक के कानून बनने के बाद निःशक्तजनों से संबंधित अधिकांश समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने वाला निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधयेक काफी व्यापक है और इसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। अब निःशक्तता में मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी शामिल। केंद्र के पास और निःशक्तता को भी शामिल करने का अधिकार होगा। दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्त नियामक के रूप में काम करेंगे। निजी कंपनियों की इमारतों में दिव्यांगों के आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना होगा।

दिव्यांगों को अब सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी आरक्षण

विधेयक में निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी गई है। विधेयक में निःशक्तजनों के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसके प्रावधान सरकार से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। गौरतलब है कि देश की आबादी के 2.2 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं। अभी तक कानून में इनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है।

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 के कानून बनने के बाद निःशक्त व्यक्तियों को काफी लाभ मिलेंगे और उनका यूनीवर्सल कार्ड बनाया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। पहले निःशक्तता से संबंधित कार्ड स्थानीय स्तर पर ही मान्य होता था। दरअसल, इस तरह के कार्ड बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है और अगले डेढ़ साल में यह काम पूरा हो जाएगा। यही नहीं, केंद्र सरकार केरल में दिव्यांग विश्वविद्यालय बना रही है और यह अगले साल से शुरू हो जाएगा।

विधेयक में निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी गई है। विधेयक में निःशक्तजनों के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसके प्रावधान सरकार से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि हमने यह प्रावधान किया है कि कोई भी दिव्यांग भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं रह पायेगा। निगरानी के लिए कोई आयोग बनाने के सुझाव के बारे में श्री गहलोत ने कहा कि आयोग केवल सलाह दे सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अधिक शक्ति सम्पन्न आयुक्तों की प्रणाली बनाने का प्रावधान किया है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होगा। इसके तहत एक केंद्रीय बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिसमें तीन सांसद होंगे।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाये गए दिव्यांग शब्द के बारे में हमने सभी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार किया और एक-दो राज्यों को छोड़कर सभी ने इस शब्द को स्वीकार करने की बात कही। विधेयक सबसे पहले फरवरी 2014 में लाया गया था। इसके बाद इसे स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 82 सुझाव दिए जिनमें से 59 सुझाव मान लिए गए। उन्होंने कहा कि विधेयक में निःशक्त व्यक्यिों को सशक्त बनाने के प्रयास किए गए हैं। निःशक्त व्यक्तियों की पहले सात श्रेणियां थीं और अब श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ■

लक्की ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना का शुभारंभ

सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में भ्रष्टाचार और काले धन के अभिशाप से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने और देश को रणनीतिक तरीके से नकदी-रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए मंत्रिमंडल ने फरवरी 2016 में कई पहलों को मंजूरी प्रदान की थी।

प्रधानमंत्री ने मई 2016 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इन उपायों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने लोगों को नकदी-रहित लेनदेन को अपनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ''यदि हम नकदी-रहित लेनदेन करना सीख लेते हैं और उसके अनुकूल बन जाते हैं तो हमें नोटों की जरूरत नहीं होगी। व्यवसाय स्वचालित हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता आएगी। गलत तरीके से लेनदेन बंद हो जाएगा जिससे कालेधन का प्रभाव कम होगा। इसलिए मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि हमें कम से कम शुरूआत तो करनी ही चाहिए। एक बार हमने शुरू किया तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। बीस साल पहले किसने सोचा होगा कि हमारे हाथों में इतने सारे मोबाइल होंगे। धीरे-धीरे हमने आदत डाली और अब हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। शायद यह नकदी रहित समाज भी ऐसा ही बन जाए। यह जितनी जल्दी होगा, उतना बेहतर होगा।

यह याद किया जाना चाहिए कि इसके लिए सरकार ने जन धन खाते खोलकर, आधार कार्ड को कानूनी आधार प्रदान करने, नकद लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन, रूपे कार्ड को जारी करके और बेहिसाब धन के लिए स्वैच्छिक घोषणा आदि संदर्भ में वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक अभियान चलाया है। 500 और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण भी इस दिशा में एक अन्य मील का पत्थर था। विमुद्रीकरण के कारण देश भर में डिजिटल भुगतानों में तीव्र वृद्धि हुई है और डिजीटल माध्यमों से लेन-देन की गई धनराशि की मात्रा और राशि में 9 नवंबर से ही कई गुणा वृद्धि देखी गई है।

वर्तमान में, भारत के लगभग 95 प्रतिशत व्यय लेन-देन नकद-आधारित होते हैं जिससे एक बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बनने के कारण सरकार को विभिन्न टैक्स लगाने और वसूलने में समस्या होती है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 8 दिसम्बर को कई उपायों की घोषणा की थी।

सरकार ने जन धन खाते खोलकर, आधार कार्ड को कानूनी आधार प्रदान करने, नकद लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन, रूपे कार्ड को जारी करके और बेहिसाब धन के लिए स्वैच्छिक घोषणा आदि संदर्भ में वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक अभियान चलाया है।

अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ाने और राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में नकदी के घातक प्रभाव को दूर करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम दीर्घावधि विचार वाली योजना बनाएं और ऐसे उपाय लेकर आएं जिससे डिजिटल भुगतान माध्यमों में ग्राहकों

के साथ-साथ व्यापारियों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब व्यावसायिक लेनदेन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके यूपीआई, यूएसएसडी, रूपे कार्ड और आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) के माध्यम से भुगतान और लेनदेन किया जा सकता है। भारत जैसा देश जहां 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से नीचे की है, जिसकी सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत सुविख्यात है और जहां गरीब और अनपढ़ लोग भी अपना वोट ईवीएम के माध्यम से डालते हैं, तो वहां पर डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करना निश्चित रूप से संभव है, बशर्ते देश के नागरिक ऐसा करने का संकल्प लें।

नीति आयोग निजी उपभोग पर व्यय के लिए डिजिटल भुगतान माध्यमों का प्रयोग करने वाले व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को नकद पुरस्कार देने की लक्की ग्राहक योजना और डिजिटल धन व्यापार योजना की घोषणा करता है। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाना है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस स्कीम को लागू करने वाली एजेंसी होगी। यह इस बात पर जोर देने के लिए उपयोगी होगा कि NPCI एक गैर लाभकारी कम्पनी है जिसे भारत को नकदी-रहित बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की जिम्मेदारी दी गई है।

इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपना सकें। इसे समाज के सभी वर्गों और उनके उपयोग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उदाहरण के लिए, गरीब से भी गरीब, व्यक्ति यूएसएसडी उपयोग करके पुरस्कारों के लिए पात्र होगा। ग्रामीण इलाकों के लोग इस स्कीम में एईपीएस के माध्यम से प्रतिभाग ले सकते हैं। यह स्कीम

25 दिसम्बर, 2016 को पहले ड्रॉ के साथ चालू हो जाएगी। यह क्रिसमस पर देश को एक तोहफा होगा। इसके बाद दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती पर एक बड़ा ड्रॉ निकाला जाएगा। इसमें दो मुख्य घटक शामिल होंगे, एक उपभोक्ताओं के लिए और दूसरा व्यापारियों के लिए:-

(क) लक्की ग्राहक योजना (उपभोक्ताओं के लिए):-

(i) 100 दिनों तक की अवधि के लिए 15,000 लक्की ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपये का ईनाम दिया जाएगा

(ii) एक लाख रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के मूल्य के साप्ताहिक ईनाम उन उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे, जो डिजिटल भुगतानों के वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करते हैं।

(ख) डिजी-धन व्यापार योजना (व्यापारियों के लिए):-

(i) व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किए गए सभी डिजिटल लेनदेन के लिए व्यापारियों के लिए ईनाम

(ii) 50,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2500 रुपये मूल्य के साप्ताहिक पुरस्कार

(ग) मेगा ड्रॉ- 14 अप्रैल, 2017 को अम्बेडकर जयंती पर

(क) 8 नवम्बर, 2016 से 13 अप्रैल, 2017 के बीच किए जाने वाले डिजिटल भुगतानों के लिए 1 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के मूल्य के 3 मेगा ईनाम 14 अप्रैल, 2017 को घोषित किए जाएंगे।

इस स्कीम का लक्ष्य छोटे लेन-देनों (सामान्य नागरिक द्वारा) के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन राशियां 50 रुपये और 3000 रुपये के बीच में किए जाने वाले लेन-देन के लिए प्रदान की जाएंगी। उपभोक्ताओं और व्यापारियों/उपभोक्ताओं तथा सरकारी एजेंसियों के बीच सभी लेन-देनों और सभी एईपीएस लेन-देनों को प्रोत्साहन योजना में शामिल किया जाएगा।

इस स्कीम के विजेताओं को एनपीसीआई द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर द्वारा पात्र लेन-देन आईडी संख्या (जो कि लेन-देन पूर्ण होते ही स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाती है।) के यादृच्छिक (क्रम रहित) ड्रॉ के माध्यम से पहचाना जाएगा। एनपीसीआई को इसके तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है, जिससे कि इस प्रक्रिया की तकनीकी अखंडता को भी सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के प्रथम चरण का अनुमानित व्यय (14 अप्रैल, 2017 तक) 340 करोड़ रुपये की संभावना है। सरकार इसके कार्यान्वयन की साथ-साथ समीक्षा करेगी। भारत तीव्र गति से नकद-आधारित समाज से नकदी-रहित समाज की ओर बढ़ रहा है। यह हमारे देश के इतिहास का ऐतिहासिक क्षण है जब हमारा देश पुरानी आदतों को छोड़ रहा है और नए माध्यमों को तीव्र गति से अपना रहा है, जो हमें वास्तविक रूप में आधुनिक युग में प्रवेश दिलाएगा। ■

अंतर्राष्ट्रीय विमानन वार्ता के दौरान छह देशों के साथ 'खुला आकाश समझौता'

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन वार्ताएं 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक नसाऊ में आयोजित की गईं। इस सम्मेलन में आईसीएओ के 191 देशों में से 106 देशों ने भाग लिया। भारत ने 17 देशों के साथ बातचीत की और 12 देशों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी 2016) में दिये गये निर्देशों के मुताबिक अनेक प्रमुख मुद्दे सुलझाये गये।

यातायात अधिकारों में वृद्धि: भारत ने ओमान के साथ यातायात अधिकारों पर फिर से बातचीत की, जिससे हकदारी में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। इसके तहत वर्ष 2017 के ग्रीष्म ऋतु से 6258 सीटें प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि मौजूदा हकदारी कमोबेश समाप्त हो गई है।

भारत ने आईएटीए सीजन से क्षमता में प्रति सप्ताह 8000 सीटों की वृद्धि के लिए सऊदी अरब से सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच यातायात में बढ़ोतरी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।

एनसीएपी 2016 के मुताबिक खुला आकाश समझौता: इस दौरान छह देशों के साथ खुला आकाश समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनमें जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं। खुला आकाश समझौते में छह महानगरों जैसेकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई स्थित हवाई अड्डों तक असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी गई है। नई व्यवस्था से भारत और इन देशों के बीच कनेक्टिविटी के साथ-साथ यात्रियों के सफर को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

नये हवाई सेवा समझौतों पर जमैका एवं गुयाना के साथ हस्ताक्षर किये गये। घाना, इजरायल, जापान, मलेशिया, पुर्तगाल, हांगकांग, इथियोपिया और बांग्लादेश के साथ हवाई सेवा समझौते से संबंधित अन्य मसलों को भी सुलझाया गया।

जीवन का ध्येय

| दीनदयाल उपाध्याय |

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर देशभर में संगोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम लगातार उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
प्रस्तुत है राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका 'पांचजन्य'(18 अगस्त, 1949) में प्रकाशित लेख का प्रथम भाग-

विश्व का प्रत्येक प्राणी सतत् इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, वह जीवित रहे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह दूसरे अनेक प्राणियों को अस्तित्वहीन करने का प्रयत्न करता रहता है तथा स्वयं उसको अस्तित्वहीन करने वाली शक्तियों से निरंतर अपनी रक्षा करता रहता है। विनाश और रक्षा के इन प्रयत्नों की समष्टि का ही नाम जीवन है। इन प्रयत्नों की भिन्नता ही भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवनों का कारण है तथा इनकी सफलता या असफलता ही विभिन्न प्राणियों के विकास या विकार का मापदंड है। मानव भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आदि मानव की सृष्टि और तब से अब तक का इतिहास इन प्रयत्नों का ही इतिहास है। किंतु मनुष्य विश्व के प्राणियों से अधिक विकसित है। उसका अस्तित्व केवल प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही निभर नहीं करता, किंतु उसके जीवन में भौतिकता के साथ-साथ आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का भी समावेश होता है। मनुष्य के जीवन का ध्येय श्वासोच्छ्वास तथा श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बनाए रखना ही नहीं है, किंतु इससे भिन्न है। वह तो श्वासोच्छ्वास मात्र जीवन को साधन मानता है, साध्य नहीं। उसका साध्य तो उपनिषदों के शब्दों में है-

'आत्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिध्यासितव्यः।'

वह आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसे समझना चाहता है; अपनी संपूर्ण क्रियाओं को उस अनुभूति के प्रति लगाता है।

मनुष्य विश्व के प्राणियों से अधिक विकसित है उसका अस्तित्व केवल प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही निभर नहीं करता, किंतु उसके जीवन में भौतिकता के साथ-साथ आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का भी समावेश होता है।

हमारी प्रेरक शक्ति

यह आत्मा क्या है, जिसके लिए मानव इतना तड़पता है? इस संबंध में अनेक मतभेद हैं और इन्हीं मतभेदों के कारण विश्व में अनेक संप्रदायों की सृष्टि हुई है। अनेक मनीषियों ने इस आत्मा को विश्व का आदि कारण, उसका कर्ता, धर्ता एवं हर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को ही माना है। उनका कथन है कि वही एकमेव शक्ति है, जो संपूर्ण विश्व को चला रही है तथा प्रत्येक प्राणी उस ओर ही बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह उसी में मिल जाना चाहता है और इसलिए मानव का प्रयत्न उस परब्रह्म का साक्षात्कार ही है। उस परब्रह्म में ही पूर्णता होने के कारण 'सत्यं शिवं और सुन्दरं' की पूर्णाभिव्यक्ति होने के कारण ही मनुष्य इन गुणों की ओर आकर्षित होता है तथा जीवन के हर क्षेत्र में इन गुणों की आंशिक अनुभूति करता हुआ पूर्ण साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है।

कुछ विद्वान् इस अदृश्य शक्ति में विश्वास न करते हुए केवल हृदय जगत् में ही विश्वास रखते हैं तथा उसमें भी मानव के विकास को (उसके सुख-साधन-संपन्न जीवन को) ही परम लक्ष्य मानकर सुख की प्राप्ति के प्रयत्नों को ही मानव जीवन का एकमेव कर्तव्य समझते हैं। उनके विचारों में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है अपितु यदि गहराई से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि मानव को एकता की अनुभूति तथा उसको सुखमय बनाने की इच्छा की प्रेरक शक्ति निश्चित ही दृश्य सृष्टि से भिन्न कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो इस दृश्य जगत् को परिव्याप्त किए हुए प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में संपूर्णता को, एकात्मता की भावना उत्पन्न करता है। उस शक्ति को आप चाहे जो नाम दें किंतु यह निश्चित है कि उसकी ओर प्रत्येक मानव अग्रसर है तथा मानवता के कल्याण की भावना किसी स्वार्थ का परिणाम नहीं, किंतु आत्मानुभूति की इच्छा का परिणाम है। अज्ञानवश मानव आत्मा के स्वरूप को संकुचित करने का प्रयत्न करता है, किंतु सत्य का ज्ञान सतत् अज्ञान पटल को भेदने के लिए प्रयत्नशील होता है।

अपनी प्रतिमा का विकास

संपूर्ण सृष्टि को एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाला मानव भी संपूर्ण मानव की आंतरिक एकता की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णानुभूति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति के साधनों एवं उनको अपने नियंत्रण में करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है, उसकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं, उसको अपनी निजी प्रतिभा का विकास हो जाता है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी एक है, किंतु उसके ऊपर स्थित पर्वत, सागर और वन उसके भिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति अपना प्रभाव उस प्रदेश के मानव पर डाले बिना नहीं रहते तथा उस विशिष्ट भू-भाग के मनुष्य पूर्णानुभूति के प्रयत्नों में अपना विकास निश्चित दिशा में करते हैं। उनका अपना एक निजी स्वत्व हो जाता है जो कि उसी प्रकार की दूसरी इकाइयों से उसी प्रकार भिन्न होता है जैसे कि एक ही सेना के विभिन्न अंग। आधुनिक युद्ध में जल, थल और वायु सेना जिस प्रकार अपनी-अपनी पद्धति से एक ही युद्ध को जीतने का प्रयत्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र एक ही मानवता की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जल, थल और वायु सेना में कार्य करने में सैनिकों को अपनी विशेष प्रतिभा का विकास होता है तथा वे अपनी निजी पद्धति से शत्रु को पराजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीनों सेनाओं में सामंजस्य रहना तो अच्छा है, किंतु यदि किसी सेना के सैनिक अपनी पद्धति को ही सत्य मानकर दूसरी सेना के सैनिकों पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें अथवा उसकी प्रतिभा को नष्ट करना चाहें तो उनका यह प्रयत्न अंतिम ध्येय की पूर्ति में बाधक होगा तथा आक्रमित सेना के सैनिकों का कर्तव्य होगा कि वे आक्रमणकारी सैनिकों से ही प्रथम युद्ध करके उनकी बुद्धि को ठिकाने पर ला दें। इसी प्रकार यदि किसी सेना के विशेष प्रभाव को देखकर अथवा किसी विशेष क्षेत्र में उनकी विजयों को देखकर अथवा आक्रमणकारी सेना की सामर्थ्य का अनुभव करते हुए कोई सेना अपनी पद्धति, अपने प्रयत्न तथा अपनी प्रतिभा को तिलांजलि देकर उस दूसरी सेना की विशेषताओं को और उसमें भी विशेषकर उसके बाह्य स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करती है तो वह तो स्वतः नष्ट हो ही जाएगी, अपितु मानव की अंतिम विजय में भी अपना दायित्व नहीं निभा पाएगी।

आक्रमण वृत्ति

विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास उपर्युक्त उदाहरण की भावनाएं ही परिलक्षित करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट पद्धति को सत्य समझने लगता है तथा अपने को ही एकमेव प्रतिभावान् मानकर दूसरे राष्ट्रों पर अपनी पद्धतियों को लादने का प्रयत्न करता है। यदि यह प्रयत्न शांतिमय होता तो भी कुछ बात नहीं, किंतु वह जबरदस्ती अपने सत्य को दूसरों के गले उतारना चाहता है। मानव के सुख और वैभव को भी वह अपने राष्ट्र के सुख और वैभव तक ही सीमित करके दूसरे राष्ट्रों के सुख और शांति को नष्ट करता है; उसके प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है। फलतः एक राष्ट्र दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे गुलाम बना लेता है।

परतंत्र राष्ट्र का जीवन प्रवाह रुद्ध हो जाता है। उसके घटक किसी-न-किसी प्रकार श्वासोच्छ्वास तो करते रहते हैं, किंतु वे अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। भौतिक दृष्टि से सुखोपभोग करनेवाले व्यक्ति भी परतंत्रता का ताप अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचती है तथा उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगती है, उनकी आत्मानुभूति का मार्ग बंद हो जाता है। युग-युगों से उनकी प्रतिभा ने प्रस्फुटित होकर जिन विशेष वस्तुओं का निर्माण किया होता है, उसकी अवमानना होने लगती है तथा उनके विनाश का पथ प्रशस्त हो जाता है। उस राष्ट्र की भाषा, संस्कृति, साहित्य और परंपरा नष्ट होने लगती है, उसके महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा निर्माण की जाती है तथा उसके नैतिक मापदंडों को निम्नतर ठहराया जाता है। उसके जीवन की पद्धतियां विदेशी पद्धतियों से आक्रांत हो जाती हैं तथा विदेशी आदर्श उसके अपने आदर्शों का स्थान ले लेते हैं। फलतः उस राष्ट्र के व्यक्तियों की दशा विक्षिप्त व्यक्ति के समान हो जाती है; अपनी प्रकृति, स्वभाव और प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की सुविधा न रहने के कारण वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से ही वंचित नहीं रह जाते, अपितु पतन की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। ■

क्रमशः

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अग्रदूत

स्वामी विवेकानंद युवा, गतिशीलता और जीवंतता के प्रतीक हैं। स्वामी जी का जीवन और आदर्श हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन में इस महान व्यक्ति ने अपने संदेश के साथ पूरे विश्व को जीत लिया। भारत और विश्व के कई महान व्यक्ति स्वामी जी से अत्यंत प्रभावित रहे।

स्वामी जी के लेखों से अनेक पाठक का मन प्रज्जवलित हुआ है। किसी ने यह बात ठीक ही जताई है कि यदि आप औंधे लेटे हों और उनके लेख पढ़ रहे हों तो आप खड़े हो जाएंगे और यदि आप खड़े होकर उनके लेख पढ़ रहे हो तो आप तुरंत ही उनके मिशन पर चलना शुरू कर देंगे। यह और कुछ नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवंत संदेश का प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति जो उनके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आया हो तो उसके जीवन में विशाल बदलाव देखने में आता है।

जीवन का प्रयोजन

स्वामी जी का सदैव यह मानना रहा है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन तभी शुरू होता है जब उसके जीवन का प्रयोजन सिद्ध होता है। वह मानते थे कि जिस व्यक्ति के पास कोई प्रयोजन नहीं होता है, तो वह तो एक जीता-जागता मात्र शव बना रहता है। जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तब तक उसका जीवन अत्यंत निरर्थक होता है।

हमारे युवाओं को तय करना चाहिए कि वे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। बचपन से ही निरंतर कैरियर के विचारों से बंधे होते हैं या हम क्या बनना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में हम जीवन में हम अच्छे पहलुओं की तरफ देखना भूल जाते हैं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम किसी संकीर्ण उद्देश्य के साथ बनने की प्रक्रिया से जीवन की प्रक्रिया को तय न करें। न बनने की बात को कभी न सोचें और इस प्रक्रिया में आप कुछ न कुछ बन ही जाएंगे। एक बार जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो जीवन के सभी कार्य उसी प्रयोजन से संचालित होते रहेंगे।

आत्मविश्वास

जीवन में कुछ भी अनुमान लगाना ही आत्म-विश्वास का द्योतक है। स्वामी विवेकानंद ईश्वर में श्रद्धा रखने से भी अधिक आत्मविश्वास को महत्व देते थे। वह कहते थे कि नास्तिक वह होता है जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता है। प्राचीन धर्म कहता है कि वह नास्तिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है, जो स्वयं में विश्वास नहीं करता है। दुर्भाग्य से हम अपनी क्षमताओं को जाने बिना ही अपने को सीमित कर लेते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम तो 'इतना भर' ही कर सकते हैं, जबकि हमारे पास कहीं अधिक करने की क्षमता होती है। यदि हमारे युवाजन निश्चय कर लें तो ऐसा विश्व में कुछ नहीं है जिस पर हम पार नहीं पा सकते हैं, परन्तु इसके लिए हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए। स्वामी जी सदैव यह मानते थे कि हमारे पास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह छोटा, बड़ा, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हो वह हमारे अन्तरतम के सामर्थ्य की अनुभूति व्यक्त करता है।

समर्पण

सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि 'सफलता के लिए आपके पास अत्यंत धैर्य आवश्यक है।'' धैर्यशाली आत्मा का कहना है कि मैं पूरा सागर पी सकता हूं, मेरी इच्छा होगी तो पहाड़ भी चरमरा कर गिर पड़ेंगे। आपके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, आप में वैसी ही इच्छा, परिश्रम और उस लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा होनी चाहिए।''

टीमवर्क

आज का युग संगठन और टीमवर्क का है। विज्ञान, व्यापारिक, टेक्नॉलाजी, टीमवर्क से एक मजबूत अधारशिला बनती है, जिसके माध्यम से हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे टीमवर्क से प्रभावित थे और वह चाहते थे कि भारत में भी टीमवर्क का भाव पुनर्शक्तिमान बन सके। इसी उदाहरण को सामने रख कर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट गए। ■

लोक सभा से 4 और राज्य सभा से 1 विधेयक पारित

संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर को आरंभ हुआ तथा 16 दिसंबर को समाप्त। सत्र के दौरान 31 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान, 10 विधेयक (सभी लोक सभा में) पुरःस्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 4 विधेयक और राज्य सभा ने 1 विधेयक पारित किया। एक विधेयक अर्थात, कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना गया। दो और विधेयक अर्थात विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016 और विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016, जिस रूप में लोक सभा द्वारा पारित किए गए थे और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजे गए थे। राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर उनके लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत इन विधेयकों को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात दिनांक 23 दिसंबर 2016 को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया माना जाएगा, जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 को भी संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया है। सत्र के दौरान पुरःस्थापित किए गए, विचार और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) तथा वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (सामान्य) और इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा की गई और उन्हें पारित किया गया। लोक सभा में वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिया गया।

लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी द्वारा "काले धन को समाप्त करने के लिए नोटों का विमुद्रीकरण" पर दिनांक 5 दिसंबर को चर्चा आरंभ की गई थी और वह पूरी नहीं हो सकी। राज्य सभा में नियम 267 के अंतर्गत नोटिस के तहत "विमुद्रीकरण"पर चर्चा हुई थी जो अधूरी रह गई। सत्र के दौरान लोक सभा में किए गए कार्य की उत्पादिता 17.39% और राज्य सभा की 20.61% रही। ■

शीतकालीन सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. नावाधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
2. किराए पर कोख देना (विनियमन) विधेयक, 2016
3. कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
4. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
5. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
7. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
8. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016
9. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
10. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

II. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
2. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
4. निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

III. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

IV. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
2. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
4. निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

V. वापस लिए गए विधेयक

1. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

पार्टी का ग्रंथालय : राजनीति की संस्कारशाला

| अमित शाह |

संगठनात्मक कार्यों से विभिन्न प्रदेशों में निरंतर प्रवास चलता ही रहता है, परन्तु इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास एक प्रमुख कारण से विशिष्टतापूर्ण रहा। 12 दिसम्बर 2016 को अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ एक विशेष कार्य का शुभारंभ हुआ। यह अवसर था जब 'नानाजी देशमुख स्मृति वाचनालय' तथा पार्टी के ई-ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं जिला कार्यालयों में बनने वाली पुस्तकालयों की श्रृंखला में यह पहला ग्रंथालय है। इसे एक आदर्श ग्रंथालय के रूप में तैयार किया गया है तथा नानाजी देशमुख जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इसका नाम 'नानाजी देशमुख स्मृति वाचनालय' रखा गया है। केवल दो महीने की अल्पावधि में निर्मित इस ग्रंथालय में विभिन्न श्रेणियों के 10,255 पुस्तकें उपलब्ध हैं। आधुनिक तकनीकों से युक्त इस ग्रंथालय में पार्टी दस्तावेज, दुर्लभ पांडुलिपियां, संविधान, इतिहास, दर्शन आदि विषयों से संबंधित अनेक पुस्तक-पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। वाई-फाई सुविधा से युक्त यहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है जहां बैठकर अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह ग्रंथालय अन्य प्रदेशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगा।

इस तरीके के ग्रंथालय अब हर प्रदेश एवं जिला कार्यालय में निर्माण हो रहे हैं। इससे पूर्व 5 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय कार्यालय में केन्द्रीय ग्रंथालय के उद्घाटन का अवसर मिला था। यह कई महीनों

के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि पार्टी मुख्यालय में एक सुव्यवस्थित ग्रंथालय का निर्माण हो पाया। एक राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी के मुख्यालय में निर्मित होने वाला ग्रंथालय हर दृष्टि से उपयोगी हो तथा पार्टी कार्यकर्ता, मीडिया के लोग, शोधार्थी, विश्वविद्यालय छात्र से लेकर किसी सामान्य पाठक के उपयोग में आये, इसका ध्यान रखा गया। एक आधुनिक ग्रंथालय की भांति इसे नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। ग्रंथालय प्रबंधन व्यवस्था के अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल ग्रंथालय (www.bjplibrary.org) भी विकसित किया गया है। इस ई-ग्रंथालय में 3620 पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं और यह किसी राजनैतिक दल की दृष्टि से दुनिया में यह पहला प्रयोग है। इसे सोशल मीडिया से भी जोड़ा गया है (@BjpLibrary)। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया है कि केन्द्रीय ग्रंथालय का जीवंत संपर्क विभिन्न प्रदेशों में स्थापित होने वाले पुस्तकालयों से हो, ताकि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाय कि पुस्तकालयों का एक व्यापक नेटवर्क पार्टी के पास उपलब्ध हो। आने वाले दिनों में यह पार्टी की बड़ी पूंजी साबित होगी।

किसी को लग सकता है कि भला राजनीतिक दल के कार्यालय में ग्रंथालय की क्या जरूरत है? यह तो राजनीतिक उठापटक का केंद्र है, रणनीति की प्रयोगशाला है या फिर मीडिया से मिलने जुलने का स्थान है। मगर मुझे बताना चाहिए कि स्वाधीनता के पूर्व और उसके पश्चात भी राजनीति में 'विचारक' राजनेताओं की एक स्वस्थ, समृद्ध परंपरा रहती आयी है। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कितने सारे राजनेता लेखक, चिंतक, कवि या विचारक भी रहे हैं। यही कारण था कि भारतीय राजनीति में जनतंत्र के प्रति आस्था बनी रही। इसी धारा को आज के वर्तमान युग में हमें हर प्रदेश में बरकरार रखना है तो लिखने-पढ़ने-अध्ययन करने वाले लोग राजनीति में आने चाहिए और राजनीति करने वालों ने लिखने-पढ़ने का अभ्यास निरंतर रखना चाहिए। यह होना है तो कम से कम हर प्रदेश कार्यालय में ग्रंथालय होना जरूरी है। ऐसे ग्रंथालय कार्यकर्ता की स्वयं-शिक्षा का प्रारंभ-बिंदु है। हम इन ग्रंथालयों से राजनीति के चित्र-चरित्र में सकारात्मक बदलाव ले आ पाएंगे, यह हमारा दृढ़ विश्वास है।

जहां तक भाजपा की बात है, इसका तो जन्म ही वैकल्पिक विचार देने के लक्ष्य के साथ हुआ। हम विचारधारा-आधारित पार्टी हैं तथा सिद्धांतों एवं मूल्यों के आधार पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं।

जहां तक भाजपा की बात है, इसका तो जन्म ही वैकल्पिक विचार देने के लक्ष्य के साथ हुआ। हम विचारधारा-आधारित पार्टी हैं तथा सिद्धांतों एवं मूल्यों के आधार पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हमारे कार्यकर्ता अपने विचार एवं सिद्धांतां को समझे, फिर उस पर पर अडिग रहें और इसके लिए निरंतर अध्ययनशील बनें। आशा है कि पार्टी कार्यालयों

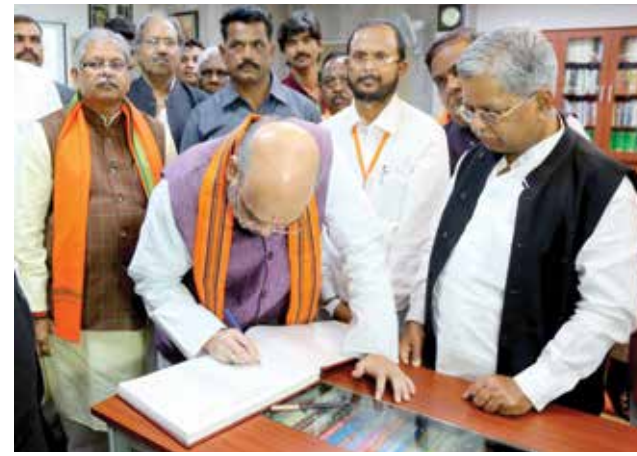

में अत्याधुनिक ग्रंथालयों के निर्माण से इस दिशा में कार्यकर्ताओं को तत्पर रहने में सहायता मिलेगी। पार्टी पुस्तकालयों से हमारे कार्यकर्ता वैचारिक रूप से और अधिक सजग, सुदृढ़ एवं परिपक्व बनेंगे और उसी से एक नयी राजनितिक संस्कृति का उदय होगा।

मेरी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वह ग्रंथालयों में आने-जाने, पढ़ने का क्रम बनाए रखें। ग्रंथालय का मूल स्वरूप 'वाचनालय' का है। यहां आकर जो पढ़ेगा, वहीं बढ़ेगा। हमने हर महीने एक या दो किताबे पढ़नी चाहिए। उस पर अपना अभिप्राय लिखना चाहिए। किताबों पर आपस में चर्चा होनी। कार्यकर्ता अपने संग्रह की किताबें, ऐसे ग्रंथालयों को भेंट करे तो और भी अच्छा। इन्हीं प्रयासों से पार्टी में वाचन की संस्कृति बढ़ेगी। देश की राजनीतिक संस्कृति बदलने की गंगोत्री ऐसे ग्रंथालयों में है, इस तथ्य को हम न भूलें। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

ब्लॉग का लिंक: ***http://base.amitshah.co.in/2016/12/24/shaping-a-new-political-culture-through-party_library/***

सुशासन की सबसे बड़ी प्रेरणा

| वेंकैया नायडू |

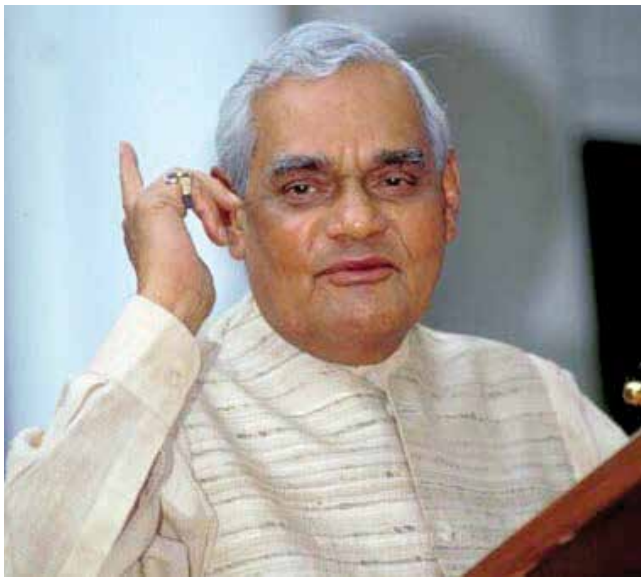

चौराहे पर लुटता चीर/प्यादे से पिट गया वजीर/चलूं आखिरी चाल कि बाजी छोड़ विरक्ति सजाऊं/राह कौन सी जाऊं मैं/सपना जन्मा और मर गया/मधु ऋतु में ही बाग झर गया/तिनके टूटे हुए बटोरूं या नवसृष्टि सजाऊं मैं/राह कौन सी जाऊं मैं? यह कुछ विचार हैं जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता 'राह कौन सी जाऊं मैं' में व्यक्त किए हैं। जब कोई व्यक्ति जनता के पास पहुंचने के लिए कठिन रास्ते को चुनता है तो उसे कई तरह की रुकावटों, उथल-पुथल और तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति इस दुविधा में पड़ सकता है कि क्या सभी बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ा जाए या पीछे लौट चला जाए। जिसके पास साहस नहीं होता वह पहली बाधा के सामने आते ही लौटना पसंद करेगा, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति वाला नेता प्रत्येक बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहेगा और अंततोगत्वा अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। अटल बिहारी वाजपेयी इसी तरह के एक विजयी नेता हैं और इससे उन्हें देशवासियों के हृदय में अमिट जगह मिली। अटलजी के लिए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। एक साधारण स्कूल शिक्षक के पुत्र वाजपेयी ने अपना कॅरियर पत्रकार के रूप में शुरू किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें उथल-पुथल भरे समय से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद वह जनता के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से नहीं डिगे।

1957 से 2009 तक वाजपेयी दस बार संसद के लिए चुने गए। जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हें हर कदम पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल में वाजपेयी ने तुच्छ राजनीतिक हितों को साधने के बजाय देश के विकास के लिए कार्यक्रमों पर अमल को प्राथमिकता दी। कम ही समय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे जनता को लंबी अवधि तक लाभ मिला। उन्होंने विश्व को दिखाया कि कैसे एक देश दशकों के कुशासन के बाद एक कुशल नेता के नेतृत्व में नई दिशा और नया आयाम प्राप्त करेगा। उनके शासनकाल पर दृष्टि डालने पर समझ में आएगा कि वाजपेयी ने कैसे देश की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कोई भी व्यक्ति उनके इस योगदान को कैसे भूल सकता है कि उन्होंने देश के बड़े शहरों को चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों तथा गांवों को सड़कों से जोड़ने का जो निर्णय लिया उससे लाखों लोगों को बिना किसी बाधा के शहरी क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिली। वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और ग्रामीण सड़क योजना निःसंदेह देश के विकास के इतिहास में मील का पत्थर है।

> वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और ग्रामीण सड़क योजना निःसंदेह देश के विकास के इतिहास में मील का पत्थर है।

वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को और जोर-शोर से आगे बढ़ाया। वाजपेयी ने हमेशा अपना ध्यान आम जनता के कल्याण पर केंद्रित रखा। वाजपेयी सरकार ने लाखों निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद छोटी सी अवधि में ही वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर विश्व को भारत की परमाणु शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भारत को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रगति के रास्ते पर भारत को आगे बढ़ते देखकर वे प्रतिबंध हटाने पर विवश हो गए। उन्होंने जहां चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया, वहीं द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिये उसके साथ सीमा विवाद के समाधान की भी कोशिश की। वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका के साथ हमारे संबंध मजबूत

नहीं थे, लेकिन वाजपेयी के शासनकाल में इसमें गुणात्मक परिवर्तन आया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ते हुए भी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा शुरू कर पड़ोसी देश के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कारगिल में उसे धूल भी चटा दी। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि तेज विकास तभी संभव है जब उपमहाद्वीप में शांति हो। कवि होने के कारण उनके व्याख्यानों में कविता सहज रूप में प्रवाहित हुई। उनकी काव्यमय भाषा, अभिव्यक्ति और शैली आम आदमी तक को आकर्षित करती है।

> अटल जी का विश्वास है कि व्यक्ति विशेष के सशक्तिकरण का अर्थ राष्ट्र का सशक्तिकरण है और यह तीव्र आर्थिक विकास और तीव्र सामाजिक परिवर्तन से आएगा।

सुशासन की अवधारणा का उद्भव कहीं और से नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ही इसके जनक हैं। न्यूयॉर्क में 7 सितंबर 2000 में एशिया सोसायटी को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने कहा था कि हमारा विश्वास है कि व्यक्ति विशेष के सशक्तिकरण का अर्थ राष्ट्र का सशक्तिकरण है और यह तीव्र आर्थिक विकास और तीव्र सामाजिक परिवर्तन से आएगा। 25 दिसंबर यानी उनके जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वाजपेयी की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कॅरियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में की। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि दोनों ही देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी ने वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है और सुशासन के उनके सपने को पूरा किया है। आखिर सुशासन है क्या? सुशासन की अवधारणा के केंद्र में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकारों की जिम्मेदारी है। देश के विकास की रूपरेखा को तय करने में समाज के सबसे कमजोर और असुरक्षित वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए। इसका संबंध पारदर्शिता, क्षमता और उत्तरदायित्व से है। सुशासन के एक अंग के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस पहल की है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी वाजपेयी द्वारा जलाई गई सुशासन की मशाल को और आगे तक ले गए हैं। ■

(लेखक केंद्रीय सूचना-प्रसारण तथा शहरी विकास मंत्री हैं)

भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा: फोर्ब्स

150 साल बाद यह पहला मौका है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। यह भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पहले अनुमान लगाया गया था कि भारत 2020 तक ब्रिटेन को पीछे कर देगा, लेकिन इसी साल हुए ब्रेक्जिट के चलते अर्थव्यवस्था की ब्रिटेन को खासी चपत लगी और पाउंड ने गोता खाया। वहीं भारत की विकास दर तेज बनी रही और वह छठे नंबर पर पहुंच गया।

विश्व प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से 2016 में भारत की जीडीपी 2.30 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.29 लाख करोड़ डॉलर।

यही नहीं, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक विकास की रफ्तार 1.8 फीसदी से गिरकर 1.1 फीसदी हो जाएगी। वहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर छह से आठ फीसदी बने रहने का अनुमान है।

गौरतलब है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। वहीं चीन और दूसरे विकसित देश बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। अनुमान है कि भारत विशाल मानव संसाधनों के चलते 2022 तक जापान, जर्मनी और फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा। ■

विमुद्रीकरण सम्बन्धी तथ्य

देश में इस पर बहस चल रही है कि क्या विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार को समाप्त करने और काले धन के उन्मूलन में मदद मिल सकेगी। इसका अर्थव्यवस्था पर अल्प, माध्यमिक और दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे लघु एवं मध्यम उद्योगों और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दैनिक मजदूरों आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़े आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई क्रांति की तरफ बढ़ें।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

विमुद्रीकरण सम्बन्धी हाल की घोषणाओं ने देश के आर्थिक परिदृश्य में भारी हलचल पैदा कर दी है। देश में इस पर बहस चल रही है कि क्या इससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने और काले धन के उन्मूलन में मदद मिल सकेगी। इसका अर्थव्यवस्था पर अल्प, माध्यमिक और दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे लघु एवं मध्यम उद्योगों और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दैनिक मजदूरों आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़े आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई क्रांति की तरफ बढ़ें। विमुद्रीकरण को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

देश में आर्थिक विकास लाने तथा भ्रष्टाचार एवं काले धन के उन्मूलन के दो महत्वपूर्ण जनादेश पर हमारी सरकार सत्ता में आई थी। वर्तमान अर्थतंत्र को ध्यान में रखकर उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हमें देखना जरूरी है:

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश का 20 प्रतिशत धन सभी परिसम्पदा वर्ग जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण तथा कैश करेंसी आदि में विद्यमान है।
- विश्व सम्पत्ति रिपोर्ट 2016 से पता चलता है कि देश की मात्र 1 प्रतिशत जनसंख्या का देश की 58 प्रतिशत से अधिक सम्पत्ति पर अधिकार है। भारत पूरे विश्व में रूस के बाद कान्सनट्रेशन आफ वेल्थ में दूसरे नम्बर पर आता है।
- हमारे देश की 97 प्रतिशत आबादी की कुल सम्पत्ति 10,000 डालर अर्थात् 7,00,000 रुपए से भी कम की है।

- भारत में नकद करेंसी का जीडीपी अनुपात 12 प्रतिशत है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कहीं अधिक है।
- सरकार का वार्षिक बजट संसाधन बहुत ही सीमित है। कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग योजनागत व्यय-इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं से निपटने के लिए किसी भी कीमत पर पर्याप्त नहीं है।
- देश का प्रत्येक नागरिक अप्रत्यक्ष करों के रूप में कर अदा कर रहा है, परन्तु यदि इस ट्रांजेक्शन को समुचित रूप से खाते में न डाला जाए तो यह आम जनता द्वारा दिया गया कर सरकार के खजाने में नहीं पहुंचेगा। इस व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए लेन-देन सम्बन्धी ट्रांजेक्शन की बैंकिंग प्रणाली में रिकार्डिंग बहुत आवश्यक है।

विमुद्रीकरण का विश्लेषण ऊपर दिये परिदृश्य को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है। आरम्भ से ही श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा

नीचे दिये गए कई उपायों में यह एक महत्वपूर्ण कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ है।

सत्ता में आते ही दूसरे दिन से सरकार ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई कड़े कदम उठाए:

1. श्री मोदी के सत्ता में आते ही एसआईटी का गठन किया गया, ताकि देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उपाए किये जाएं।
2. विदेशी अवैध परिसम्पदा घोषणा योजना।
3. मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय कर संधियों पर पुनः वार्ता, जिस के माध्यम से अधिकांश हवाला कारोबार होता था।
4. फाटका; FATCA के अन्तर्गत वित्तीय सूचना साझा करने के लिए अमेरिका के साथ संधी।
5. (OECD) और जी20 देशों के साथ वित्तिय सूचना के आदान-प्रदान करने के लिए मोदी जी की पहल।
6. इनकम डिस्क्लोजर प्लैन (आईडीएस)
7. बेनामी परिसम्पत्ति के कानूनों के प्रावधानों का पारित किया जाना, जोकि पिछले दस वर्षों से लम्बित पड़ा था।
8. संसद के वर्तमान सत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम एवं व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम में संशोधन का बिल पेश करना।
9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाना, यह उन लोगों को दण्डित करने के लिए है, जो बैंकिग चैनलों में काला धन वर्तमान में घोषित करते हैं।
10. अभी के ढाई वर्षों में लगभग 92 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर दण्डित किया गया है जो विगत वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

काले धन के उन्मूलन और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए विमुद्रीकरण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह देश के सभी भौगोलिक हिस्सों में एवं समाज के आम आदमी के आर्थिक विकास के लिए समान एवं पारदर्शी अवसरों को प्रदान करने की प्रक्रिया का एक जरिया है।

विमुद्रीकरण के लाभ

- भारी मात्रा में कैश करेंसी के सर्कुलेशन के कारण अर्थव्यवस्था पर मांग का भारी दबाव था, जिसके चलते आवास आदि महंगे हो गये थे, आम आदमी का घर का सपना उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। विमुद्रीकरण से रियल एस्टेट की कीमतें घटेंगी तथा इससे सभी प्रकार की महंगाई भी कम होगी।
- गरीबों और अल्प आय ग्रुपों एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और सामाजिक योजनाओं के लिए सरकार को अधिक संसाधन प्राप्त होंगे।
- इससे कम ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी, आवासीय ऋण, गरीबों के और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम दरों पर ऋण मिल सकेंगे।
- जीएसटी जिससे की अप्रत्यक्ष करों को कम करने में मदद मिलेगी, उसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए ढांचा तैयार होगा।
- नकली करेंसी को अर्थव्यवस्था से हटाया जा सकेगा, आतंकवादी, माओवादी घटनाएं और लूट-खसोट जैसी आपराधिक गतिविधियां पर लगाम लगेगा।
- ऑनलाइन भुगतान तथा मोबाइल बैंकिंग के द्वारा जो ट्रांजेक्शन होती है उसकी कीमत प्रति ट्रांजेक्शन काफी कम बैठती हैं। इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा (ऑनलाइन भुगतान पर सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम के तहत जागरुकता की नई पहल की गई हैं)
- लोगों द्वारा कर अनुपालन का स्तर देश में बढ़ेगा।

काले धन के उन्मूलन और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए विमुद्रीकरण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह देश के सभी भौगोलिक हिस्सों में एवं समाज के आम आदमी के आर्थिक विकास के लिए समान एवं पारदर्शी अवसरों को प्रदान करने की प्रक्रिया का एक जरिया है।

तीसरी तिमाही की कर रिपोर्ट से पता चलता है:

- अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

सरकार करेंसी की आवाजाही की कमी से पूर्ण रूप से अवगत है, परन्तु इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। हम लोगों से ऑनलाइन भुगतान और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम द्वारा कम नकद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं, परन्तु हम इसे लोगों में जागरूकता के द्वारा करेंगे, इसे अनिवार्य नहीं बनाएंगे। सरकार सिस्टम में कैश करेंसी खत्म नहीं कर देगी, परन्तु उसे जीडीपी का लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक रखने का प्रयास करेगी।

सरकार इस बात से भलीभांति अवगत है कि करेंसी की इस कमी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

इसलिए सरकार द्वारा जीडीपी के विकास और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का रोडमैप तैयार है:

(क) बैंकों के चालू खाते और बचत खातों में जमाधन की वृद्धि होगी। इससे बैंकों के पास जमा धन कि कीमत कम होगी और इसके परिणाम स्वरूप सस्ते दर के फंड की उपलब्धता बढ़ेगी।

(ख) लघु एवं मध्यम क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप, स्टैंडअप, मुद्रा ऋण कम ब्याज दरों पर दिया जाए इस पर ध्यान दिया जाएगा।

(ग) रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट और ईएमआई का रेट कम करने से आवास आम लोगों की पहुंच में आ सकेगा तथा इससे निर्माण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) अधिक कर अनुपालन से सरकार कराधान के दर कम करने की तरफ बढ़ सकेगी और पहली बार ईमानदारी का फल लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा।

(ङ) काले धन के संचालन के कारण अर्थव्यवस्था में कई विसंगतियां आ गई हैं, इसे खत्म करने का प्रयास तभी पूर्ण सफल होगा जब लोग पुराने कालेधन को नई करेंसी में कन्वर्ट न कर सकें। इसीलिए सरकार कुछ कठोर नियमावलियों को ला रहीं हैं।

(च) करापूर्ति में वृद्धि और अधिक संसाधनों से, सरकार भारी निवेश कर सकेगी और सामाजिक क्षेत्र में व्यय से आम आदमी के जीवन की उत्कृष्टता में भी सुधार आएगा।

(छ) जीएसटी के कार्यान्वयन से अप्रत्यक्ष करों में कमी आएगी। इसके लिए सही इकोसिस्टम की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार वातावरण बना रही है, ताकि लेन-देन को समुचित पारदर्शी रूप से रिकार्ड किया जा सकें। ■

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

संकट नहीं समाधान है नोटबंदी

1999 से 2004 तक के राजग शासनकाल के दौरान सालाना 5.5 प्रतिशत के हिसाब से वास्तविक जीडीपी की विकास दर 27.8 प्रतिशत थी। सालाना धन आपूर्ति जो मुद्रास्फीति का वाहक है, 15.3 प्रतिशत रही। कीमतें सालाना 4.6 प्रतिशत के हिसाब से 23 प्रतिशत बढ़ीं। इन पांच वर्षों में संपत्ति की कीमतें मामूली दर से बढ़ीं। स्टॉक 32 प्रतिशत की दर से बढ़ा। सोने की कीमतें 38 प्रतिशत की दर से बढ़ीं।

एस गुरुमूर्ति

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उसे अभूतपूर्व विफलता करार दिया है। इस आशय का एक लेख लिखते समय वह अर्थशास्त्री की तरह कम, पूर्व प्रधानमंत्री की तरह अधिक दिखे हैं। कोरी बयानबाजी नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर यह निर्णय होना चाहिए कि विमुद्रीकरण आफत है या उपचार? यह अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व कुप्रबंधन है जैसा कि डॉ. सिंह आरोप लगा रहे हैं या यह सत्तर सालों की जमा हुई गंदगी का इलाज है जैसा कि नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं? इसका उत्तर जानने के लिए 1999 से 2004 तक के राजग और 2004 से 2014 तक के संप्रग शासनकाल की अर्थव्यवस्था पर निगाह डालनी होगी। 1999 से 2004 तक के राजग शासनकाल के दौरान सालाना 5.5 प्रतिशत के हिसाब से वास्तविक जीडीपी की विकास दर 27.8 प्रतिशत थी। सालाना धन आपूर्ति जो मुद्रास्फीति का वाहक है, 15.3 प्रतिशत रही। कीमतें सालाना 4.6 प्रतिशत के हिसाब से 23 प्रतिशत बढ़ीं। इन पांच वर्षों में संपत्ति की कीमतें मामूली दर से बढ़ीं। स्टॉक 32 प्रतिशत की दर से बढ़ा। सोने की कीमतें 38 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। चेन्नई को उदाहरण के रूप में लें तो वहां जमीन की कीमतें 32 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। करीब 600 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं। 2002 से 2004 के दौरान व्यापार संतुलन में भारत को 20 अरब डॉलर का सरप्लस भी हासिल हुआ।

अब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई वाले संप्रग के शासनकाल पर आते हैं। घपलों-घोटालों में घिरने से पहले 2004 से लेकर 2010 तक संप्रग शासनकाल में सालाना 8.4 प्रतिशत के हिसाब से जीडीपी की वृद्धि दर 50.8 प्रतिशत थी, जो राजग के शासनकाल की तुलना में डेढ़ गुना अधिक थी। इसे लेकर दुनिया ने डॉ. सिंह की भरपूर सराहना की। संप्रग उच्च विकास दर को देखकर

मुग्ध था, लेकिन आखिर संप्रग के उच्च विकास दर ने नौकरियां कितनी पैदा कीं? एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार तब देश में सिर्फ 27 लाख नई नौकरियां पैदा हो पाई थीं, जबकि राजग के पांच साल के कार्यकाल में 600 लाख नई नौकरियां पैदा हुई थीं। संप्रग ने राजग से डेढ़ गुना अधिक विकास दर हासिल की, पर नई नौकरियां पैदा होने की दर सिर्फ पांच प्रतिशत रही। अब डॉ. सिंह विलाप कर रहे हैं कि मोदी सरकार का विमुद्रीकरण का फैसला नौकरियों को खत्म करेगा? राजग के समय 4.6 प्रतिशत की तुलना में संप्रग के 2004 से 2010 तक के कालखंड में कीमतें 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर रहा, जबकि राजग के समय यह 20 अरब डॉलर सरप्लस था। क्या इसके लिए पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंची कीमतें जिम्मेदार थीं? नहीं, बल्कि सीमा शुल्क की शून्य दर ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रेरित किया।

संप्रग के वक्त उच्च विकास दर रोजगारविहीन क्यों थी? दरअसल संपत्ति की ऊंची कीमतें, मुद्रास्फीति और उत्पादन में कमी ने उच्च विकास दर के प्रभाव को धूमिल किया था। संप्रग के पहले छह साल के कार्यकाल में स्टॉक और सोने की कीमतों में तीन गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। संपत्ति की कीमतें हर दो साल में दोगुनी हो गईं। गुड़गांव, जो 1999 में संपत्ति के नक्शे पर नहीं था, में जमीन की कीमतें दस से बीस गुनी बढ़ गईं। छह सालों में संपत्ति में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक जीडीपी की विकास दर की तीन गुना अधिक थी। जमीन-जायदाद की कीमतों में मुद्रास्फीति परिणाम नहीं थी, बल्कि संप्रग की उच्च विकास दर का कारण थी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पैसा, विकास, कीमतें और रोजगार आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब राजग और संप्रग के शासन में इस नियम को लागू कीजिए। 2004 से 2010 के बीच औसत धनापूर्ति में वार्षिक 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजग के समय यह 15.3 प्रतिशत थी, लेकिन संपत्ति की कीमतें इससे कई गुना बढ़ीं। राजग के समय धनापूर्ति में सामान्य वृद्धि संपत्ति की कीमतों में विशाल बढ़ोतरी को बयान नहीं करती है। असली बात बिना निगरानी वाले पांच सौ और हजार रुपये के नोटों की भारी-भरकम संख्या में छिपी हुई है। 1999 में लोगों के पास मौजूद पैसा जीडीपी का महज 9.4 प्रतिशत था। 2007-08 तक बैंक और डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी के बावजूद यह आंकड़ा 13 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके बाद यह 12 प्रतिशत के आसपास बना रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के पास मौजूद बड़े नोटों का जो प्रतिशत 2004 में 34 था वह 2010 में 79 प्रतिशत तक पहुंच गया। आठ नवंबर 2016 को यह आंकड़ा 87 प्रतिशत था।

रिजर्व बैंक ने गौर किया है कि 1000 के नोटों का दो तिहाई और पांच सौ के नोटों का एक तिहाई (जो मिलकर छह लाख करोड़ रुपये है) जारी होने के बाद से कभी बैंकों में नहीं पहुंचा। बैंकों से बाहर मौजूद यह बड़ी राशि काले धन के रूप में सोने और संपत्तियों में इधर से उधर होती रही। इसका एक हिस्सा पार्टिसिपेटरी नोट के जरिये भी इधर-उधर होता रहा। भारत के बाहर अक्सर यह कारोबार हवाला के रूप में होता है। इसका कुछ भाग शेयरों में विदेशी निवेश के रूप में आया। गौर करने लायक है कि 2004 में पार्टिसिपेटरी नोट की राशि 68 हजार करोड़ रुपये थी, जो 2007 तक बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये हो गई।

संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि से उपजे रोजगाररहित विकास के अभिशाप से छुटकारा तब तक असंभव था] जब तक बिना निगरानी वाले ऊंची कीमत के नोट चलन में बने रहते। इससे फर्जी विकास को मदद मिलती है। मनमोहन सिंह को कई बार जागने के मौके मिले। उन्हें तभी जाग जाना चाहिए था जब 2004 के बाद से हर साल ऊंची कीमत वाले नोटों का हिस्सा बढ़ता जा रहा था। वह बिना किसी रोकटोक के तेजी से फैल रही कैश इकोनामी को थाम सकते थे, अगर उन्होंने ऊंची कीमत वाले नोटों के स्थान पर कम मूल्य वाले नोटों के चलन को बढ़ावा दिया होता। तब उन्हें नोटबंदी जैसे कदम को भी नहीं उठाना पड़ता] जिससे न तो जनता को परेशानी उठानी पड़ती और न ही अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक नुकसान उठाना पड़ता। हां, इससे उन्हें उस कथित विकास से जरूर वंचित होना पड़ता, जिसे संप्रग शासन की सफलता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थव्यवस्था में हो रही इस धोखाधड़ी को उजागर करने और रोजगार उत्पादक विकास को फिर से जिंदा करने के लिए बिना निगरानी के चल रहे ऊंची कीमत वाले नोटों को बलपूर्वक बैंकिंग के दायरे में लाने की जरूरत थी, लेकिन अपनी निष्क्रियता से मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े भंवर में फंसा दिया। मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे। एक, मौजूदा स्थिति को जारी रखते हुए उसी राह पर आगे बढ़ते रहना या दूसरा, असली विकास और नौकरियों को वापस लाने के लिए विकास में अस्थायी गिरावट का रास्ता चुनना। मोदी सरकार ने दूसरी राह चुनी है। ■

अर्थव्यवस्था में हो रही इस धोखाधड़ी को उजागर करने और रोजगार उत्पादक विकास को फिर से जिंदा करने के लिए बिना निगरानी के चल रहे ऊंची कीमत वाले नोटों को बलपूर्वक बैंकिंग के दायरे में लाने की जरूरत थी, लेकिन अपनी निष्क्रियता से मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े भंवर में फंसा दिया। मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे। एक, मौजूदा स्थिति को जारी रखते हुए उसी राह पर आगे बढ़ते रहना या दूसरा, असली विकास और नौकरियों को वापस लाने के लिए विकास में अस्थायी गिरावट का रास्ता चुनना। मोदी सरकार ने दूसरी राह चुनी।

(लेखक जाने-माने अर्थशास्त्री एवं विचारक हैं) *(दैनिक जागरण से साभार)*

न्यायालय ने की तीन तलाक पर सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत के अनेक न्यायालयों में तलाक से पीडित अनेक मुस्लिम महिलाओं ने राहत के लिए दर्द से भीगी हुई अर्जियां लगाई हुई हैं। साथ ही तीन तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय के भीतर और इतर अन्य समुदायों के बुद्धिजीवी चिंतक और सुधारकों के बीच बहस चल रही है।

| डॉ. सुधा मलैया |

आफ्रीन, सबाना, फर्जाना और शाहीन की आंखो में आंसू थे। किंतु इस बार ये आंसू छले जाने, ठगे से खड़े रह जाने के नहीं थे। रंजोगम से डूबी पहाड़ सी जिंदगी अकेले काटने के चिंता के भी नहीं थे। ये खुशी के आंसू थे। उस देश की धरती ने उनके साथ न्याय किया जहां उन्होंने या उनके बुजुर्गों ने धर्म के नाम पर विभाजन के पश्चात् रहना चुना, क्योंकि एक बार फिर धर्मनिरपेक्ष भारत की न्यायपालिका ने पुनः धर्मनिरपेक्ष निर्णय लेने का साहस किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की भावना के अनुरूप मुखर स्वरों में साफ कर दिया कि भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और तीन तलाक कह देने मात्र से मुस्लिम महिला को तलाक दे देना, न केवल गैरकानूनी है अपितु वह असंवैधानिक भी है। कोई भी धर्म या पर्सनल लॉ बोर्ड का निर्णय संविधान से ऊपर नहीं है और तीन बार मौखिक तलाक मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, और असंवैधानिक भी है।

किंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत के अनेक न्यायालयों में तलाक से पीडित अनेक मुस्लिम महिलाओं ने राहत के लिए दर्द से भीगी हुई अर्जियां लगाई हुई हैं और तीन तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय के भीतर और इतर अन्य समुदायों के बुद्धिजीवी चिंतक और सुधारकों के बीच बहस चल रही है। बहस का केंद्र बिंदु यद्यपि तलाक है किंतु अंतिम परिणति में चर्चा का विषय समान नागरिक संहिता का लागू होना ही है। इसी के क्रियान्वयन से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक की त्रासदी से मुक्त हो सकती हैं।

किंतु जैसी कि आशंका थी सियासतदानों ने, जिन्होंने मुस्लिम भावनाओं को भड़का कर वर्षों राजनीति की है, इस निर्णय को भी

उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़ने का कुत्सित राजनीति प्रारंभ कर दी है। प्रत्येक निर्णय, चाहे किसी भी न्यायालय का हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी काल में हो, किसी के पक्ष में और किसी के विरुद्ध होगा ही। धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष में भी किसी भी सैद्धांतिक अवधारणा के पक्ष और विपक्ष में लोग होते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समाज में भी अनेक लोग अब वर्तमान युग में तीन तलाक के पक्ष में नहीं हैं। तो क्या कोई भी न्यायालय किसी सुधार के पक्ष में निर्णय न दे इस डर से कि उसका निर्णय के अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से राजनीतिक दल निकालेंगे। यदि आज के दिन सती प्रथा जारी रहती और हिंदू समाज के कोई भी कट्टरवादी या संकीर्ण सोच के लोग इसको समाप्त करने के विरुद्ध आवाज उठाते तो क्या वह उचित होता। जो लोग भी तीन तलाक का विरोध कर रहे हैं वे संवेदनारहित हैं और निर्मम हैं। स्वार्थी हैं वे जिन्हें केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है। उन्हें चार–चार, पांच–पांच बच्चे लेकर उम्र के आधे पड़ाव पर घर से बाहर निकाल दी जाने वाली महिला की आहें नहीं सुनाई पड़ती, उसकी दर्द भरी साँसों की आवाज नहीं सुनाई देती। बच्चे को पालने की, अपना भरण पोषण करने की और रात–दिन समाज के ताने सुनने की, बिना कारण अपने को अपराधी मानने की त्रासदी नहीं दिखती। जो देश को गाली देने वालों और उसकी बर्बादी के नारे लगाने वालों और देश की संसद पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उन्हें मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा क्या समझ में आयेगी।

ऐसी स्थिति में यदि देश हित में अहर्निश सोचने, बैठने, सोने और उठने वाला मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मुस्लिम महिला की पीड़ा और उसकी यातना के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता है, तो क्या गलत करता है? इन महिलाओं की पीड़ा समस्त राजनीतिक दलों का सरोकार क्यों नहीं है? दलगत भावना और राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर राजनीतिक संवेदना का विषय ये कब बनेगा उनके लिए।

स्पष्ट कानूनों के अभाव में तीन बार मौखिक तलाक अथवा वाट्सएप अथवा फैसबुक अथवा पोस्टकार्ड अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गये तलाक के कारण घर से बेदखल की गयी महिला की पीड़ा को समझने का दायित्व केवल भाजपा का क्यों हो, प्रत्येक राजनीतिक दल क्यों नहीं? क्यों न वे उसके दर्द, पीड़ा को महसूसे और हाईकोर्ट के निर्णय के पक्ष में दृढ़ता से खड़े हों। किंतु फिर वही बात जो अपनी मातृभूमि के सगे नहीं, उन राजनीतिक दलों का क्या धर्म और क्या ईमान। देशभक्ति, स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम, पीड़ा, दर्द उन्हें क्या मालूम। आश्चर्य तो इस बात का है जिन दलों की कमान और नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है–मायावती, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी–उनके द्वारा भी इस निर्णय के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलना क्या कहता है? उनकी खामोशी क्या संदेश देती है? कि वे उनकी पीड़ा नहीं समझती? मुस्लिम महिलाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण है ये।

समय है कि हम चेतें। अवसर है कि सरकार और विपक्ष दोनों संसद के दोनों सदनों में मिलकर समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस प्रारंभ करें। वर्तमान सरकार इसकी साहसिक पहल करे। इस मत विभाजन होता है तो हो, परिणाम कुछ भी निकले किंतु देश की एक बड़ी जनसंख्या को लकीर का फकीर बनाये रखने वालों के चेहरे तो बेनकाब हों। मुस्लिम महिलाओं ने अंगड़ाई ली है, वे मुखर होने लगी हैं, खुद–मुख्तार बनने लगी हैं। इसके साथ ही एक बड़ा पढ़ा–लिखा मुस्लिम वर्ग भी इन खब्ती कानूनों से तंग आ चुका है और बदलाव चाहता है। किंतु उनकी आवाज कठमुल्लों की द्वारा दशकों से दबायी जा रही है। आशाजनक सिर्फ यह है कि यदि यह सरकार कोई पहल करेगी तो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थन करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यह पहल किसी का तुष्टिकरण करने के लिये नहीं, अपितु सुधार की दिशा में उठाया गया कदम होगा।

मुस्लिमों की दुर्दशा का आकलन करने के लिये गठित आयोगों और समितियों ने जितने भी मुस्लिमों के पिछड़ेपन के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक कारण गिनाये हैं, वे सब इसी से जुड़े हुए नहीं हैं? सामाजिक कारण क्या हैं? क्या निजी कानून और शरीयत की आड़ में किये जा रहे जुल्म इसी से जुड़े हुए हैं राजनीतिक और आर्थिक कारण भी। आयोगों समितियों की भाषा में ओर कानून की भाषा में अंतर हो सकता है किंतु आशय और भावार्थ तो वहीं है। भाषा अनेक हो सकती हैं भाव तो एक ही है। पंथ अनेक हो सकते हैं लक्ष्य तो एक है।

धर्मनिरपेक्ष देश में जो जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, हिंदू और मुसलमानों के लिये अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, ये सबको पता है। न्याय और समता तो तभी स्थापित हो सकती है जब कानून एक से हों और वे राजनीतिक विवशता से प्रेरित न हो।

जब तक मुस्लिम समुदाय राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष देश में जो जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, हिंदू और मुसलमानों के लिये अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, ये सबको पता है। न्याय और समता तो तभी स्थापित हो सकती है, जब कानून एक से हों और वे राजनीतिक विवशता से प्रेरित न हो और वक्त इस बात का भी है कि अब भारत डेढ़ सौ साल से चले आ रहे अंग्रेजों द्वारा बनाए कानूनों की भी पुनःव्याख्या करे। देश की जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों में फेरबदल करे और ऐसे सब कानूनों का बहिष्कार करें जिनसे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव होता है। एक व्यक्ति जिस अपराध के लिये जेल जा सकता है दूसरा व्यक्ति उसी कृत्य को करने के बाद भी बाहर रहता है, क्योंकि उसका निजी कानून है, तो यह गलत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा तीन तलाक के मामले में की गयी सुनवाई न्यायोचित है। समयानुकूल है और मूलभूत अधिकारों तथा लैंगिक समानता की दृष्टि से सर्वथा उचित है। इस सुनवाई का, निर्णय का स्वागत होना चाहिए। ■

(लेखिका भाजपा राष्ट्रीय पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग की सदस्य हैं।

मलेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध हमारी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का अभिन्न हिस्सा: नरेंद्र मोदी

द इकनॉमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को कहा, 'हाल में हमने सामरिक भागीदारी सुनिश्चित की है। पिछले साल नवंबर में मेरी मलेशिया यात्रा से तमाम क्षेत्रों में इस सामरिक भागीदारी को बल मिला। मलेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध हमारी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का अभिन्न हिस्सा है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड एवं लाइन ऑफ क्रेडिट सहित भारत की तमाम पहल से भारत-आसियान सहयोग को काफी प्रोत्साहन मिला है।' यहां हम अपने सुधी पाठकों के लिए उनके संबोधन के मुख्य अंश को प्रकाशित कर रहे हैं।

महामहिम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मलेशिया 2020 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के साथ सामंजस्य में भी उसने लचीलापन दिखाया है। भारत और मलेशिया के बीच कालातीत संबंधों को बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय की मौजूदगी से बल मिल रहा है।

कुआलालंपुर के हृदयस्थली में तोरण द्वार हमारे एतिहासिक संबंधों का हालिया प्रतीक है जो दो महान राष्ट्रों और दो महान संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। हाल में हमने सामरिक भागीदारी सुनिश्चित की है। पिछले साल नवंबर में मेरी मलेशिया यात्रा से तमाम क्षेत्रों में इस सामरिक भागीदारी को बल मिला। मलेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध हमारी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का अभिन्न हिस्सा है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड एवं लाइन ऑफ क्रेडिट सहित भारत की तमाम पहल से भारत-आसियान सहयोग को काफी प्रोत्साहन मिला है।

आसियान देशों के नेताओं ने इस क्षेत्र के देशों के बीच बेहतर एकीकरण के लिए प्रयासों का नेतृत्व किया है। इसलिए एशिया के कारोबारी दिग्गजों को एक साथ लाने की यह पहल बिल्कुल ठीक समय पर की गई है। मैंने कई अवसरों पर कहा है कि इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है। एशिया जहां काम करने के लिए हाथ हैं, खपत के लिए परिवार और सीखने के लिए प्रमुखों की विनम्रता है। प्रतिकूल एवं अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद भी एशियाई क्षेत्र में विकास की संभावनाएं उम्मीद की एक किरण है।

भारत फिलहाल एक आर्थिक बदलाव का गवाह है। यह न केवल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि यह इन गतिविधियों को लेकर भी चर्चित रही है:

- कारोबारी सुगमता,
- पारदर्शी एवं कुशल प्रशासन और

- नियामकीय बोझ में कमी।

वर्तमान में व्यवस्था से कालेधन और भ्रष्टाचार की सफाई मेरे एजेंडे में सर्वोपरि है। डिजिटलीकरण और जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद ऐसा किया गया है। हमारे प्रयासों के परिणाम विभिन्न संकेतकों पर भारत की वैश्विक रैंकिंग से दिखाई रहे हैं। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। हम भारत में कारोबारी माहौल और विश्व के बेहतरीन माहौल के बीच खाई को तेजी से पाट रहे हैं। हम UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में वर्ष 2016-18 के लिए शीर्ष संभावित मेजबान अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे पायदान पर हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2015-16 और 2016-17 के हमारे रैंक में 32 पायदान का सुधार हुआ है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2016 की हमारी रैंकिंग में 16 पायदान और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2016 में 19 पदों का सुधार हुआ है। हमने एफडीआई के लिए नए क्षेत्रों को खोल दिया है और मौजूदा क्षेत्रों के लिए सीमा बढ़ाई है। प्रमुख एफडीआई नीति में सुधार के लिए हमारे ठोस प्रयास जारी हैं और निवेश के लिए शर्तों को सरल बनाया गया है। परिणाम सबके सामने हैं।

पिछले ढाई वर्ष के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पिछले साल एफडीआई निवेश अब तक का सर्वाधिक रहा। पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान एफडीआई इक्विटी निवेश में उससे पिछले दो वर्षों के मुकाबले 52 फीसदी वृद्धि हुई। एफडीआई निवेश आकर्षित करने वाले स्रोतों और क्षेत्रों भी व्यापक विस्तार हुआ। इस साल हमारे 'मेक इन इंडिया' अभियान का दो वर्ष पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

पिछले ढाई वर्ष के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पिछले साल एफडीआई निवेश अब तक का सर्वाधिक रहा। पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान एफडीआई इक्विटी निवेश में उससे पिछले दो वित्त वर्षों के मुकाबले 52 फीसदी वृद्धि हुई।

यहां मैं अपनी कुछ उपलब्धियों को उजागर करना चाहता हूं:

- अब हम दुनिया में छठा सबसे बड़ा विनिर्माण देश बन गए हैं।
- हमारे सकल मूल्यवर्द्धन में 2015-16 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- पिछले दो वर्ष के दौरान 51 कोल्ड चेन परियोजनाएं पूरी की गईं और 2014 के बाद छह मेगा फूड पार्क खोले गए।
- पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान 19 नए टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है और मौजूदा टेक्सटाइल पार्कों में 200 नई उत्पादन इकाइयां लगाई गईं।
- भारत में विनिर्मित मोबाइल फोनों की संख्या में इस साल 90 प्रतिशत का उछाल आया।
- वाहन क्षेत्र के प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों ने तमाम नई असेंबली लाइन एवं ग्रीनफील्ड इकाइयां स्थापित की हैं।
- भारत में कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास का दायरा व्यापक और विस्तृत है जिसमें कानूनी और ढांचागत सुधार भी शामिल है।

आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वस्तु एवं सेवाकर के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। इसे 2017 में लागू होने की उम्मीद है। हम एक डिजिटल एवं नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। हमारी लाइसेंस व्यवस्था को काफी युक्तिसंगत बनाया गया है। व्यापार पंजीकरण, एग्जिम मंजूरी और श्रम अनुपालन के लिए हमने एकल खिड़की इंटरफेस शुरू किया है। पानी और बिजली जैसी सुविधाएं हासिल करने के लिए प्रक्रियाएं आसान बनाई जा रही हैं। निवेशकों के मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ बनाया गया है। मेक इन इंडिया शुरू होने के बाद राज्य सरकारों के साथ हमारी भागीदारी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विश्व बैंक के साथ मिलकर राज्यों को उनकी व्यापार नीतियों एवं प्रक्रियाओं के मानदंडों पर 2015 में हुई सहमति के आधार पर आंका गया। इसमें 2016 में और विस्तार किया गया। हमने पहली बार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की है, ताकि बौद्धिक संपदा के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके। हमने 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम कंपनियों के पुनर्गठन और बाहर निकलने के लिए नियमों को आसान बना रहे हैं।

दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता का अधिनियमन और उसे लागू करना भारत में कारोबार से बाहर होने के नियमों को आसान बनाने की ओर उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्यिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नई वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना की जा रही है। कार्यवाही में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता कानून में भी संशोधन किया गया है। भारत फिलहाल उद्यमशीलता गतिविधियों से भरा पड़ा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। स्टार्टअप भारत की अगली बड़ी आर्थिक ताकत है और यह किसी क्रांति से कम नहीं है। हमारे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में हमारी क्षमता का खुलासा करना है। हमारी आर्थिक प्रक्रिया उन गतिविधियों से संचालित हो रही है जो रोजगार सृजन और स्वरोजगार की संभावनाओं के लिए काफी अहम हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने का एकमात्र रास्ता है।

कौशल भारत अभियान और उसके विभिन्न घटकों के माध्यम से हम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना फिलहाल हमारे हाथ का सबसे बड़ा काम है। हम देशभर में औद्योगिक कॉरिडोर का पंचभुज विकसित कर रहे हैं। देशभर में लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

देशभर में सड़क, रेलवे एवं बंदरगाह का उन्नयन किया जा रहा है। इस प्रकार के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए हमने विदेशी फंडों के साथ मिलकर राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष की स्थापना की है। यह एकीकरण का समय है। खुलेपन के बिना एकीकरण नहीं हो सकता। भारत हमेशा से खुले दिलवाला रहा है। ■

प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूरा करने के लिए जी-जान से जुट गया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को कानपुर में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल रही है और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूरा करने के लिए जी-जान से जुट गया है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश के गांव, गरीबी, किसान, दलित, पिछड़े एवं युवाओं के प्रति समर्पित है।

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनों को संभालने में लगी रही, देश को संभालने में उनकी रूचि ही नहीं थी। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि एक तरफ हमारा एजेंडा देश से भ्रष्टाचार और काले-धन को ख़त्म करना है, वहीं विपक्षी पार्टियों का एजेंडा संसद को बंद रखने का है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश के बाद भी इन लोगों ने शोर-शराब कर संसद को नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनके लिए हिसाब देना ज़रा महंगा पड़ रहा था इसलिए उन्होंने संसद नहीं चलने दी। उन्होंने देशवासियों को आगाह करते हुए कहा कि संसद की गरिमा को अपने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास काफी गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि पहले भी संसद की कार्रवाई में रुकावटें आती थीं, लेकिन ये रुकावटें तब आती थीं जब विरोधी दल मिलकर बेईमानों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए संसद की कार्रवाई को ठप्प किया। आज विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश दो हिस्से में बंटा हुआ है। एक तरफ कुछ मुट्ठी भर नेता हैं जो कालेधन-भ्रष्टाचार और बेईमानों को बचाने में लगे हैं, दूसरी तरफ पूरा हिन्दुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जिनको आदत बेइमानी की पड़ी है, उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि काला धन, काला मन, काला कारोबर ने ही मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों का हक छीना है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो गरीबों को उनका हक़ दिलाना चाहती है, मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहती है।

श्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने गरीबों को लूटा है, 8 नवंबर के बाद से वे परेशान हैं और गरीबों के पैरों में पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि

राजनीतिक दलों के चंदे को लेकर कांग्रेस ने 45 साल पहले कानून बनाया था, जिसमें मौजूदा सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, 'जब सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तब उनके बारे में कहा जाता था कि न खाता न बही, जो केसरी कहें वही सही। ये उनके हिसाब किताब के तरीके थे।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी देश की जनता को हिसाब नहीं दिया, भ्रष्टाचार को पनपने दिया, खुद के फायदे में जो था वही किया और इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवर्तन की यह आग पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी की तरह चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। राज्य के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, हर तरफ अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों के मकान छीने जा रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, जब तक उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी, अपराधी तत्त्वों के ठिकानें नहीं बदलने वाले हैं।

> परिवर्तन की यह आग पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी की तरह चल रही है। यूपी में सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। राज्य के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, हर तरफ अराजकता का माहौल है।

श्री मोदी ने कहा कि हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग दो दर्जन ही ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। अकेले उत्तर प्रदेश में 35 लाख से अधिक गरीब परिवारों में गैस कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान समय पर होना शुरू हो गया है, किसानों के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड की योजना लागू की गई है और यूरिया की नीम कोटिंग के जरिये इसकी कालाबाजारी और सिंथेटिक दूध के कारोबार को ख़त्म करने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। ■

नोटबंदी से नुकसान उनका हुआ है जिनके घर में अरबों-खरबों का भ्रष्टाचार से अर्जित रुपया रद्दी में बदल गया है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के एटा में आयोजित विशाल परिवर्तन रैली को संबोधित किया और यूपी के विकास के लिए राज्य की जनता से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज एटा की धरती पर मैं बाबू कल्याण सिंह को याद कर रहा हूं, क्योंकि उनके शासन में उत्तर प्रदेश में गुंडे दिखते नहीं थे, वे या तो जमीन के अंदर थे या फिर राज्य के बाहर।

श्री शाह ने कहा कि अखिलेश जी, यूपी की जनता आपसे नोटबंदी पर नहीं, बल्कि आपके पांच सालों के शासन का हिसाब चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अखिलेश यादव से पूछना चाहती है कि राज्य के अंदर लोगों पर हुए फर्जी मुकद्दमों का जिम्मेवार कौन है? उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अखिलेश यादव से यह जानना चाहती है कि मथुरा के अंदर जमीन हथिया ली गई। पूरे प्रदेश में गरीबों की जमीनें हड़प ली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा क्या इसके लिए राज्य की अखिलेश सरकार जिम्मेवार नहीं हैं? उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप एक बार प्रदेश में समाजवादी सरकार को उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दीजिये, लगभग एक ही सप्ताह में सारे भू-माफ़िया जमीन छोड़ कर भाग खड़े होंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कितनी शर्मनाक बात है कि बुलंदशहर में सड़क पर बहन-बेटियों के साथ बलात्कार की निंदनीय घटना होती है और समाजवादी सरकार के बड़बोले मंत्री आजम खान उसका मखौल उड़ाते हैं, अखिलेश बाबू, आप उसका जवाब दीजिये। उन्होंने कहा कि इसी एटा में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, उसका जवाब दीजिये अखिलेश जी। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि चाचा भतीजे के कमीशन खाने के चक्कर में प्रीमियम ही नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं में केवल एक ही वर्ष में 161% की वृद्धि हुई है, पूरे प्रदेश में अराजकता फ़ैली हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में वर्ग तीन और वर्ग चार में नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने इंटरव्यू ख़त्म नहीं किये, क्योंकि इससे तो उनकी दुकान ही बंद हो जाती।

नोटबंदी के मसले पर कांग्रेस एंड कंपनी पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश, मायावती, राहुल, केजरीवाल, ममता - सब के सब नोटबंदी की माला जप रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर तक ये सारे मोदी जी से पूछते थे कि मोदी जी, आपने कालेधन के लिए क्या किया, आज पूछते हैं कि मोदी जी, कालेधन के लिए आपने यह क्यों किया। उन्होंने कहा कि 'क्या किया' से 'क्यों किया' के बीच में क्या है, यह देश की जनता को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से नुकसान उनका हुआ है जिनके घर में अरबों-खरबों का भ्रष्टाचार से अर्जित रुपया रद्दी में बदल गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश, मायावती, राहुल, केजरीवाल, ममता - नोटबंदी से ये सभी एक हो गये हैं पर सबके चेहरे का रंग बदल गया है, बहन जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, अखिलेश जी को कोई होश नहीं है, ममता जी तिलमिलाई हुई है और राहुल गांधी तो हर रोज पैदल मार्च निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी, यदि आपको मार्च ही निकालना है तो रोजगार के लिए निकालिए, भुखमरी से लड़ाई के लिए निकालिए, गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए निकालिए, गांवों की सड़कें बनाने के लिए निकालिए, काले धन को बचाने के लिए तो मत निकालिए।

> आप एक बार प्रदेश में समाजवादी सरकार को उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दीजिये, लगभग एक ही सप्ताह में सारे भू-माफ़िया जमीन छोड़ कर भाग खड़े होंगे।

श्री शाह ने कहा कि आज अखिलेश यादव कहते हैं कि यदि कांग्रेस हमारे साथ आ जाय तो यूपी में शायद फिर से हमारी सरकार आ जाए, अरे भाई, बुआ को क्यों छोड़ते हो, बुआ-भतीजा, राहुल सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ■

कारोबार को आसान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत सरकार के देश में कारोबार के माहौल में सुधार लाने के प्रयासों और विश्व बैंक की रिपोर्ट में कारोबार करने में आसान करने के दर्जे में सुधार लाने के लिए 19 दिसंबर को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहरी विकासमंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण, बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव सहित डीईए, डीआईपीपी, एमसीए, न्याय, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राजस्व, भूमि संसाधन विभाग, सीबीईसी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

डीआईपीपी के सचिव ने बताया कि नोडल विभाग ने देश के रैंकिंग में सुधार करने वाले 10 सूचकों में प्रत्येक सूचक की पहचान की गई है जो देश में सुधार प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विभागों ने इस बैठक में हाल में किए गए सुधारों का संक्षिप्त अवलोकन पेश किया गया और वर्ष 2017 में सुझावों को क्रियान्वित करने पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि विभाग हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करेगा और सुधार पर उठाए गए कदम पर उनका फीडबैक प्राप्त करेगा। विभाग फीडबैक देने वालों के साथ बातचीत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सुधार जमीनी स्तर पर महसूस किए जाएं। इस संदर्भ में प्रत्येक विभाग आवश्यक सुधार करने के लिए इस दिशा में होने वाली प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करेगा।

इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय :

1. कारोबार शुरू करने के लिए ई बिज पोर्टल आवश्यक होगा। इनमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तीनों सेवाएं पैन और टैन के लिए पंजीकरण, ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण भी शामिल है।

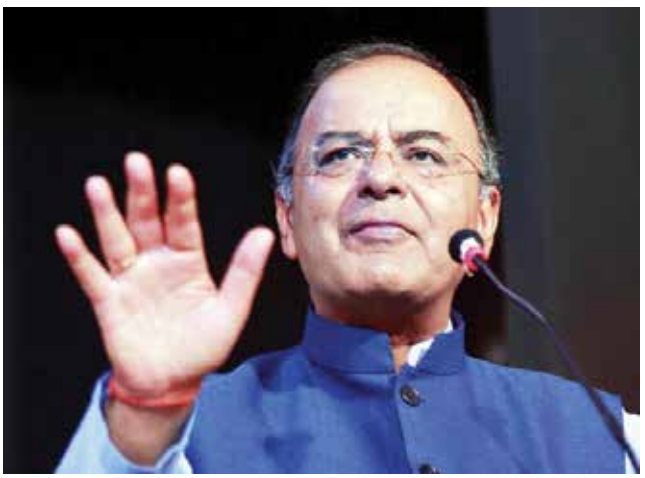

नोडल विभाग ने देश के रैंकिंग में सुधार करने वाले 10 सूचकों में प्रत्येक सूचक की पहचान की गई है जो देश में सुधार प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विभागों ने इस बैठक में हाल में किए गए सुधारों का संक्षिप्त अवलोकन पेश किया गया।

2. कारोबार शुरू करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सीबीडीटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रक्रियाओं की संख्या कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें प्रक्रियाओं की संख्या 4 की जाएगी और इसके लिए दिन भी चार तय किए गए हैं।

3. रिर्टन दाखिल करने, चालान,ऑनलाइन भुगतान,और ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंशदान के लिए केवल श्रम सुविधा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकेगा।

4.राजस्व विभाग और जहाजरानी मंत्रालय प्रत्यक्ष वितरण के खेप की संख्या इस महीने तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने के लिए काम करेंगे। विभाग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि निर्यात और आयात की लागत में ठोस कमी आए, जिससे भारत दुनिया के 50 शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो सके।

5. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर एनसीएलटी के माध्यम से हाल ही में बने तालाबंदी और दीवालिया संहिता के प्रावधानों को लागू करेगा।

गौरतलब है कि सुधार में होने वाली प्रगति की समीक्षा के लिए अगले साल जनवरी में फिर बैठक होगी ताकी स्वीकृत समय सीमा के भीतर इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ■

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किए 100 दिन पूरे

'नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रगतिकामी कदम उठा रहे हैं'

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री विजय रूपाणी ने 7 अगस्त को कार्यभार संभाला। पिछले 100 दिनों के बीच गुजरात को एक आदर्श राज्य बनाने हेतु श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने कई प्रगतिकामी और बहुआयामी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने किसानों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं और वंचितों के समेकित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं–

वर्षा की कमी से जूझ रहे सौराष्ट्र और गुजरात के मध्य भाग में खड़ी फसल को बचाने के लिए 10 घंटों की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। एक अन्य निर्णय में वर्तमान बिजली उपभोग सीमा के भीतर किसान दो मोटर चला सकते हैं।

- गुजरात सरकार ने सिंचाई और खेती को बेहतर बनाने के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए 32 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है।
- देश में शायद पहली बार जाति, वर्ग और धर्म का भेदभाव किए बिना नौजवानों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि आवंटित की है।
- अब 100 प्रतिशत अंधे दिव्यांग भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्रेणी में विद्या सहायक की भर्ती में पात्रता के योग्य होंगे।
- यदि खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की सरकारी अस्पताल में मौत हो जाती है, तो गुजरात सरकार उसके शव को पूरे सम्मान व सहानुभूति के साथ उसके घर तक पंहुचाने में आए खर्च की जिम्मेदारी लेगी।
- गुजरात सरकार पोरबंदर और नवसारी के बीच समुदी सीमा पर काम करने वाले मछुवारे और नाविकों को 80 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी मुहैया कराएगी।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत 1.55 लाख गर्भवती महिलाओं को वित्तीय मदद दी गई।
- गुजरात सरकार द्वारा पुलिस फोर्स समेत सभी सरकारी पदों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और इसके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने 6000 गावों को हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टीविटी से जोड़ा है।
- गुजरात के 3 जिले, 30 तालुके, 170 टाउन एरिया और 3000 गांव खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं।

- संघीय सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में गुजरात प्रदेश के दो शहर– सूरत और राजकोट देश के 10 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं।
- चिरंजीवी योजना के तहत 11 लाख गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया गया।
- उच्च–रक्त चाप और मधुमेह पीड़ित रोगियों को जीवन भर मुफ्त देने की योजना का सफल कार्यान्वयन किया गया।
- सरदार सरोवर नर्वदा योजना की अति शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस समय गेट बनाने का कार्य चल रहा है। इस योजना को पूरा होने से तमाम नगरों को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। किसानों को अधिक जल मिलेगा तथा गुजरात में समृद्धि आएगी।
- 13900 नए जलाशयों और 183 जल संशोधन संयंत्रों को निर्मित होने से गुजरात राज्य की जल धारण में 300 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के निर्धारित वेतन पाने वाले कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार होने पर 2 लाख रुपये की कैशलेस मेडिकल सहायता उपलब्ध होगी। ■

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2)............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास-कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

उत्तर प्रदेश में परिवर्तन रैलियों को संबोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

शाहजहांपुर

एटा

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

वित्त मंत्रालय

भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ लड़ाई के लिए कैशलेस भुगतान की ओर बढ़ा भारत

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन

डिजिटल बनिए, लाभ उठाइए

केंद्र सरकार की पेट्रोलियम पीएसयू पर डिजिटल भुगतान करने पर **0.75%** की छूट

2016-17 में नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान के लिए आरएफआईडी कार्ड/ फास्ट टैग्स का इस्तेमाल करने पर **10%** की छूट

उपनगरीय रेल नेटवर्क पर **1** जनवरी **2017** से मासिक या सीजनल टिकट की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर **0.5%** की छूट

ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर **10** लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा

2000 रुपये तक की लेन-देन पर किसी प्रकार का डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज/ एमडीआर नहीं लगेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के उपभोक्ता पोर्टल से बेची गई बीमा प्रीमियम पर **10%** तक की क्रेडिट या छूट

नाबार्ड की मदद से सरकार **4.32** करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'रुपे किसान कार्ड' जारी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों की सहायता करेगी।

नाबार्ड के माध्यम से सरकार ऐसे एक लाख गांवों, जिनकी आबादी **10,000** से कम है, वहां कम से कम **2** पीओएस डिवाइस लगाने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये है कि डिजिटल भुगतान पर लगने वाले ट्रांजेक्शन शुल्क/एमडीआर का भुगतान उपभोक्ता नहीं बल्कि सरकार वहन करे।

कैशलेस भुगतान के 5 आसान तरीके

कार्ड्स, पीओएस

आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम

यूपीआई

प्रीपेड वॉलेट

यू.एस.एस.डी

मेरा मोबाइल... मेरा बैंक... मेरा बटुवा...

ज्यादा बचत, ज्यादा सुविधा